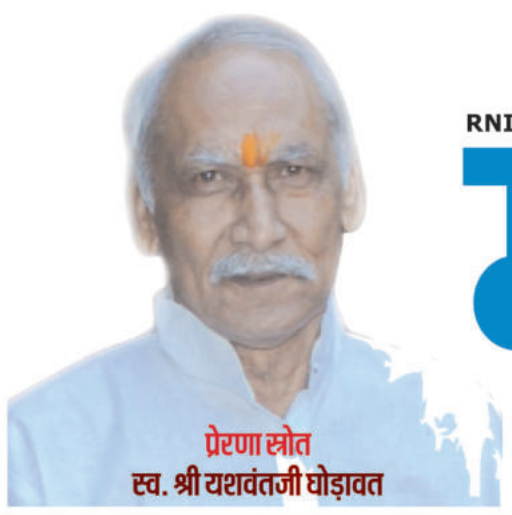

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी भ्रम में नही रहना चाहिए। क्योंकि बिना गुरू के कोई भी व्यक्ति आज तक आगे नहीं बढ़ सका।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

वर्ष-08, अंक - 29 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 07 मई 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

पश्चिम बंगाल में भाजपा की विजय, माइक्रो मैनेजमेंट, सत्ता विरोधी लहर का असर

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

2014 के बाद से ही भाजपा की विजय का अश्वमेघ घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन दक्षिण में अभी तक भाजपा अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई है। और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का किला अभी तक भाजपा के लिए अभेद गढ़ था। लेकिन उस अभेद गढ़ में सेंध लगाने का कार्य किया है भारतीय राजनीति के चाणक्य देश के गृहमंत्री अमित शाह ने तथा उनके माइक्रो मैनेजमेंट ने। जहां उन्होंने न केवल प्रत्येक बूथ का बारीकी के साथ विश्लेषण किया बल्कि प्रत्येक बूथ के लिए अलग-अलग रणनीति के तहत योजना बनाई। महज दो सीटों से 77 व 77 से 207 तक पहुंचना भाजपा के लिए रातों-रात नहीं हुआ बल्कि उनके लिए 15 साल की मेहनत रंग लाई है। निःसंदेह भारतीय राजनीति में अमित शाह की रणनीति का लोहा आने वाले समय में राजनीति पंडित राजनीतिक मिसाल के रूप में मानेगें।

2026 बंगाल जीत का असर

किसी भी चुनाव परिणाम का असर दुरगामी राजनीति पर अवश्य पड़ता है, 2026 में बंगाल में भाजपा की जीत 2029 के चुनावो पर असर डालेगी यह तय है। 2024 के चुनाव में भाजपा अपने बुते बहुमत से कुछ दूरी पर रह गई थी, वजह थी उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम हो गई थी। बंगाल और बिहार इस कमी को पूरा कर सकते हैं, शायद इसीलिए भाजपा का पूरा जोर बंगाल पर था। बिहार की राजनीति में वह छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। उसी प्रकार बंगाल में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनना 2029 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की निर्भरता को कम करेगा। अगले वर्ष 6 राज्यों में चुनाव होना है जिसमें से अधिकांश भाजपा के कब्जे में ही है। ऐसे में इन राज्यों में वापसी के साथ ही बीजेपी हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बनाम सम्मान करना चाहेगी। बंगाल चुनाव में जिस प्रकार ममता दीदी हठधर्मिता दिखा रही है वह उनकी राजनीति अपरिपक्वता को दर्शा रहा है। ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से बंगाल में मुख्यमंत्री है और चुनाव हारने के बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगी, ऐसा कहकर वो अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचय दे रही है। हालांकि वो स्वयं यह जानती है कि, इस्तीफा न देने की स्थिति में क्या कार्रवाई हो सकती है...? राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में इस हठधरमिता से उनकी ही फजीहत हो सकती है। संविधान की दुहाई देने वाली ममता दीदी का यह व्यवहार निश्चित रूप से उनकी हार की बौखलाहट को दर्शा रहा है। वो न केवल अपनी सीट बचा पाई बल्कि पार्टी को भी नहीं जीता सकी। अगर उन्हें लगता है कि, उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वह अपना विरोध संवैधानिक तरीके से कर सकती है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी वो अपनी बात रख सकती है।

झालमुड़ी पूरे देश में चर्चित

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक प्रधानमंत्री द्वारा एक दुकान पर पहुंचकर झालमुड़ी खाने का वीडियो पूरे देश में प्रचारित हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि, झालमुड़ी उन्होंने खाई लेकिन उसकी मिर्ची पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को लगी। चुनाव परिणाम के बाद पूरे देश में भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया जिसमें मिठाई के साथ ही झालमुड़ी भी खिलाई गई जिसके बाद झालमुड़ी राष्ट्रीय डिश बन गई। वास्तव में झालमुड़ी देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नाम से जानी जाती है। पश्चिम मध्य प्रदेश में इसे सेव परमल के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा खाए जाने के बाद अचानक झालमुड़ी राजनीतिक स्टेटस सिंबल बन गई।

कितना सुरक्षित है मध्यप्रदेश का यातायात...?

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले दिनों घटित दो घटनाओं ने मध्यप्रदेश के यातायात सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। अमूमन हर घटना के बाद सरकार द्वारा सिस्टम में सुधार का दावा तो किया जाता है लेकिन समय के साथ वह दावा धुंधलाता जाता है, जब तक की कोई नई घटना घटित न हो जाए। मध्यप्रदेश के धार जिले में लोडिंग वाहन में क्षमता से अधिक लोग बैठे थे और वह काल के गाल में समा गए। कहने को तो मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग है और हर चीज के लिए नियम बने हुए हैं लेकिन उन नियमों का पालन कराने वाले अधिकारी, कर्मचारी कुंभ करणी नींद में है जो अमूमन घटना होने के बाद ही हरकत में आते हैं। घटना के होने के बाद पूरा सिस्टम हरकत में आता है और आनंन-फानंन में सक्रियता दिखाई जाती है जो समय के साथ वापस सुस्त अवस्था में आ जाती है। धार के साथ झाबुआ व आलिराजपुर जिले के संदर्भ में देखें तो आमतौर पर यहां ओवरलोडिंग और लोडिंग वाहनों में ठूस-ठूस कर सवारी भरना आम बात है। बात करे लोंडिंग वाहनो की तो नियमानुसार उसमें पेसेजर बिठाना ही अपराध है लेकिन धार,झाबुआ,आलिराजपुर आदि इन जिलो में छोटे लोडिंग वाहनो में ठुस-ठुस कर पेसेंजरो को भर कर आवाजाही होती है। ये ही नहीं एक मोटरसाइकिल पर 4 से 5 सवारी बैठना भी आम बात है। ऐसे में धार के साथ झाबुआ-आलिराजपुर जिले के परिवहन विभाग को भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है...?

दूसरी घटना जबलपुर की है यहां बरगी डैम में दर्दनाक क्रूज हादसा हुआ। तेज आंधी-तूफान के कारण 20 साल पुराना क्रूज पलट गया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में लाइफ जैकेट की कमी और सुरक्षा गाइडलाइंस की अनदेखी सामने आई है। क्रूज में लाइफ जैकेट पहनने के बाद ही बैठने का सामान्य नियम है और इसी नियम की अनदेखी की गई और हादसा हो गया। अब सवाल यह उठता है कि, इन नियमों का पालन करवाने वाले आखिर अपनी जिम्मेदारी का वहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं...? नियमों की अनदेखी का खामियाजा आखिर कब तक निर्दोष लोग भुगतते रहेंगे...?

मोहन सरकार : लाचार विधायक

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और कई नगरीय इलाकों में तथा ग्रामीण इलाकों में जनप्रतिनिधि भी भाजपाई ही है। ऐसे में हम उन इलाकों में ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं। लेकिन हालत देखिए ट्रिपल इंजन सरकार में सत्ता पक्ष के विधायक लाचार बने हुए हैं और वे अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हुए ग्रामीणों के लिए सड़क बनाने के लिए मंत्री के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सहज ही कल्पना की जा सकती है, मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में नौकरशाही कितना हावी है कि, यहां सत्ता पक्ष के ही विधायक की नहीं सुनी जा रही है, तो आम जनता की क्या कल्पना कर सकते हैं...?

क्या है मामला

2 मई 2026 को आयोजित रतलाम विकास प्राधिकरण (आरडीए) के पदभार ग्रहण समारोह में रतलाम ग्रामीण से भाजपा विधायक मथुरालाल डामर ने मंच से अपनी ही सरकार के सिस्टम पर तंज कसते हुए बेबाकी से अपनी बात रखी। जिसमें उन्होंने कहा कि, छोटे-मोटे विधायकों की बात मंत्री नहीं सुनते हैं वे अपने क्षेत्र में सड़क बनवाने के लिए मंत्री राकेश सिंह के पास जाते हैं लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। और मंत्री जी के पीए आवेदन फेंक देते हैं। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गहरे संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि, ग्रामीणों की उन्नति और विकास से ही शहरों की खुशहाली भी जुड़ी हुई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कों की बदहाली और सिंचाई के लिए डैम (बांध) की

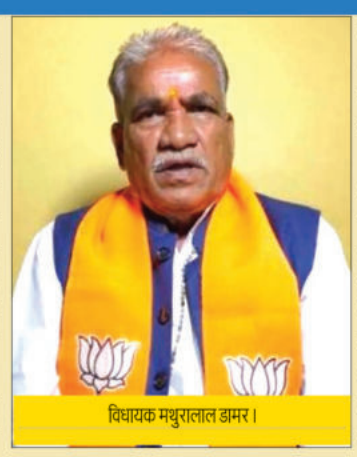

विधायक मथुरालाल डामर।

स्वीकृति की मांग की। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र की उपेक्षा का दर्द बयां करते हुए कहा कि, ग्रामीण समृद्ध होगा तभी रतलाम शहर भी मुस्कुराएगा।

उन्होंने रतलाम शहर विधायक को उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप के सामने हाथ जोड़कर मांग की, हमारा रोड भी बनवा दीजिए और रतलाम शहर के साथ मेरे ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करवा दीजिए। यही नहीं विधायक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि, दर्द होता है कि, मैं विधायक हूं भाजपा के 165 विधायक है और छोटे-मोटे विधायक को तो मंत्री पहचानते ही नहीं है।

उल्लेखनीय है रतलाम ग्रामीण के मथुरालाल डामर दूसरी बार के विधायक है। पहली बार उन्हें 2013 में टिकट मिला था और जीते थे। 2018 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था तब उन्होंने अपनी ही पार्टी पर कई आरोप भी लगाए थे। 2023 में पुनः उन्हें टिकट दिया गया और वे दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। मथुरालाल डामर अपनी देसी स्टाइल और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर कई बार वे मंचो से अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर चुके हैं। वरिष्ठ होने से क्षेत्र में वे बॉ के नाम से पहचाने जाते हैं।

ये केवल एक विधायक का दर्द ही नहीं आम आदमी का भी दर्द है कि, मध्यप्रदेश में नौकरशाही इतनी अधिक हावी हो चुकी है कि, जनता के वाजिब कामों के लिए भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। चुनाव के समय भाजपा ने नारा दिया था कि, एमपी के मन में मोदी और चुनाव के बाद मोदी के मन में मोहन आ गए। लेकिन मोहन राज में नौकर शाही बेलगाम हो गई है और विधायक तक सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अधिकारियों से मिलने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है ऐसे में आम जनता किसके भरोसे...?

स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च, स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बल

नई दिल्ली।

देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'स्वस्थ भारत पोर्टल' लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल को एक आधुनिक और एकीकृत स्वास्थ्य ढांचे की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित यह पोर्टल देश के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही मंच पर लाने का कार्य करेगा। अब तक अलग-अलग डिजिटल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग की जाती थी, जिससे डेटा बिखराव और संसाधनों के दोहराव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। 'स्वस्थ भारत पोर्टल' इन चुनौतियों का समाधान करते हुए 'वन-स्टॉप' प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।

यह पोर्टल एपीआई-आधारित फेडरेटेड आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है, जो विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को आपस में जोड़ता है। इससे इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार होगा और डेटा का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को अब अलग-अलग पोर्टल पर लॉगिन करने या बार-बार डेटा एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय की बचत और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

इस पहल से देश के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैसे आशा, एएनएम, सीएचओ और मेडिकल ऑफिसर सीधे लाभान्वित होंगे। उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग और निगरानी की सुविधा मिलेगी। साथ ही, पोर्टल में डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी शामिल किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान होगी।

स्वस्थ भारत पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप विकसित किया गया है और इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के साथ इंटीग्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। भविष्य में इसे हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से भी जोड़े जाने की योजना है,

जिससे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का सुरक्षित और सहज आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सकेगा।

सरकार के अनुसार, इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना पर होने वाले खर्च में 20 से 30 प्रतिशत तक और डेटा एंट्री व मानव संसाधन से जुड़ी दोहराव वाली प्रक्रियाओं में 20 से 40 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है।

बंगाल जीतः प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने दी बधाई

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में इस बार ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिला है जिसकी गूंज सात समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गई। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ के ढहने पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास अंदाज में बधाई दी। ट्रंप ने इस जीत को ऐतिहासिक और निर्णायक बताया है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि जिस राज्य में दशकों तक तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों का प्रभाव रहा, वहां अब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बड़ी जीत के लिए स्वयं संदेश भेजकर बधाई दी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत खुशकिस्मत है जिसे मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। उनका यह संदेश दर्शाता है कि बंगाल की इस जीत की गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुनाई दे रही है।

294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वही 1 सीट पर 21 मई को दोबारा चुनाव होना है। जानकारों के अनुसार यह जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर भवानीपुर और नंदीग्राम से सामने आई, जहां भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ भवानीपुर में 15 हजार से अधिक मतों से पराजित किया।

नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव बना रहा। ममता बनर्जी की यह हार तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।

वोट चोरी: कभी सीटें तो कभी पूरी सरकार चुरा ली जाती है-राहुल गांधी

नई दिल्ली।

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद देश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कभी वोट चोरी से सीटें तो कभी सरकार चुरा ली जाती है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स' पर संदेश साझा करते हुए कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, तो कभी पूरी सरकार। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के 240 लोकसभा सांसदों में से लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी के जरिए जीता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को भाजपा की भाषा में घुसपैठिया कहा जाना चाहिए। हरियाणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पूरी सरकार ही घुसपैठिया है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि, जो संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं और मतदाता सूचियों व चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करते हैं, वे खुद दूरस्थ नियंत्रण से संचालित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ दल को सच्चाई का डर है, क्योंकि यदि निष्पक्ष चुनाव हों तो भाजपा 140 सीटों के आसपास सिमट सकती है।

इससे पहले भी राहुल गांधी चुनावी नतीजों के दौरान कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां चुनाव चुराए गए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखी गई है। वोट चोरी के आरोप के बीच ममता बनर्जी ने भी भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 100 से अधिक सीटें लूटी गईं और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। इन आरोपों के बीच चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

सट्टेबाजी से युवाओं में दुष्प्रभाव : ऑन लाइन सट्टा बाजार पर सरकार सख्त और कड़े कानून लाए

माही की गूंज, झाबुआ।

सट्टे की सड़क पर युवाओं की तेज रफ्तार अंत में उनसे सबकुछ छील लेती हैं। यहां तक की कभी तो युवा अपने आप को भी दांव पर लगा देता है और सट्टेबाजी में हार के बाद निराशा होने से युवा अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार की समाज में हानि होने पर ऑनलाइन सट्टा बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सामाजिक रुप से जो क्षति होती है उसका ये सटोरिएं अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए सरकार को सट्टेबाजी पर सख्त कानून लाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में बच्चों में ऑनलाइन गेमींग का प्रभाव इस स्तर पर फैला हुआ है कि, ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चें जीद्दी और हठी स्वभाव के हो गए है। साथ ही साथ मानसिक रुप से अत्यंत कमजोर भी हो गए है। इसके साथ ही सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम में ऑनलाइन सट्टे से जुड़े विज्ञापन बच्चों और युवाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं, और बहुत सी बार युवा उन गेम्स के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अधिकतर माता-पिता की शिकायत आती है कि, उनके बच्चों से गेमींग में हजारों व लाखो रुपए खर्च हो गए। कहीं-कहीं जब युवाओं से लगाया गया पैसा गेम और ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से वापस नहीं आता है तो पारिवारिक और सामाजिक डर के कारण वे अपनी जान गवां देते हैं। ऐसे में घर का चिराग बुझ जाता है मगर समाज में ऑनलाइन सट्टा बाजार में चलता रहता है।

युवाओ के साथ भी स्थिती कुछ इस प्रकार से होती है कि, ऑनलाइन सट्टे की शुरुआत में युवा पहले पहल पर तो जीत जाता है फिर जब वह निरंतर सट्टा खेलने लगता है तो फिर हार उसे औंधे मुंह नीचे गिरा देती है। आज के समय में युवा अपने मोबाइल फोन पर ढ़ेरो एप ऐसे रखता है जो ऑनलाइन सट्टा या तीन पत्ती या क्रिकेट का खेल खिलवाकर पैसो का हेर-फेर करने के साथ सट्टा या जुआ खिलवाते हैं।

सट्टेबाजी में लोग पहले भी हार कर अपनी पुंजी, अपनी जमीन, यहां तक की चल-अचल संपत्ती को भी बेच देते थे। आज के दौर में वही सारी चीजे फेशन के दौर से गुजरती हुई दिखाई देती है और सट्टा खेलने वाला धीरे-धीरे सड़क पर आ जाता है। अंततः उसके पास खाने को भी नहीं बचता हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी से युवाओं में फैलते दुष्प्रभाव का अभी तक कोई उचित या प्रभावशील समाधान नहीं आया है। सरकार ने पहले भी बहुत से ऐसे एप को बंद कर दिया था जो युवाओं को सट्टे और जुए के रंगीन भंवर में डालते थे लेकिन सरकार ने जितने सट्टा एप बंद किए उससे ज्यादा तो नए फिर से शुरु हो गए।

ऑनलाइन सट्टेबाजी का शिकार तो सभी वर्ग के युवक, युवतियां हो रहीं है लेकिन शर्म के कारण अपने सम्मान को यथावत रखने की चाह में मध्यम वर्गीय युवा सट्टे में हानि या भारी क्षति होने पर स्वयं को काल का ग्रास बना देता है।

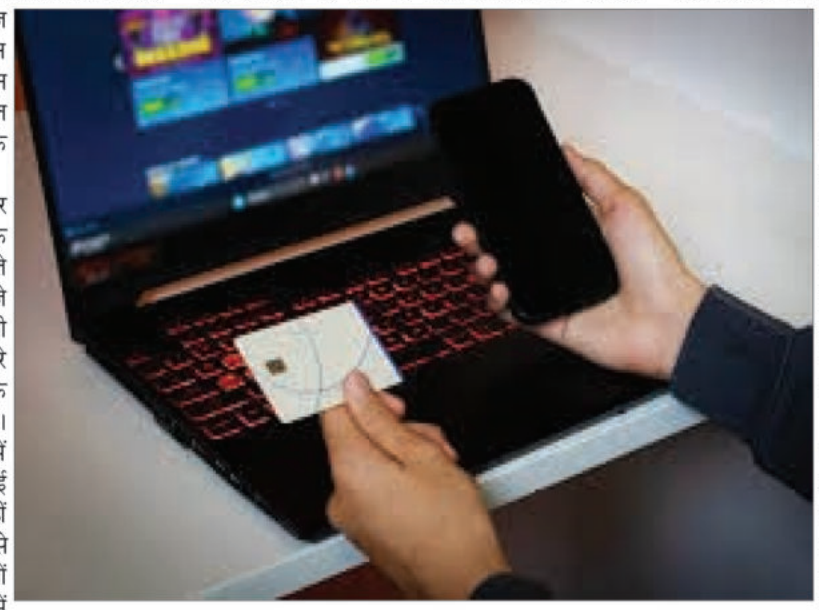

कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत से युवा सट्टे की लत में पड़कर उधार पैसा लेते हैं, और स्वयं को ब्याज के चक्रव्युह में फंसा लेते हैं। ऑनलाइन सट्टे बाजी के लिए युवा ऑनलाइन लोन लेते हैं, और फिर हार जाने के बाद सिर पटक कर रोते हैं। जो धनवान युवा होते हैं वो तो अपने पेरेंट्स को कुछ तो भी झुठ बोल कर पैसा मंगवा लेते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। निर्धन युवा ज्यादा से ज्यादा अपनी स्कॉलरशीप का उपयोग करते हैं, और नहीं तो पढ़ाई छोड़ वो दिहाड़ी मजदूरी करना शुरु करते देते हैं या फिर वे युवा अपराध की दूनिया में कदम रखते हैं। सरकार द्वारा निर्धन युवा के लिए की गई सारी मेहनत सट्टे के बाजार में लूट जाती है और निर्धन युवा ऑनलाइन सट्टा बाजार में आ कर सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पाता और अपनी स्थिती में सुधार भी नहीं ला पाता।

सट्टेबाजी में लंबी सौदेबाजी अगर हो जाती है तो हार के बाद मान, प्रतिष्ठा पर प्रश्न और दाग के कारण वो अपनी मौत को गले से लगा लेते हैं। सट्टे बाजी, जुएं बाजी में युवा अपराध की राह को थाम लेते हैं। सट्टे में हुई किसी प्रकार की भी हानि वो गलती है जिसे फिर से सुधारा नहीं जा सकता है।

सट्टे बाजी के इतने सारे दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम होने पर भी सरकार, कोई ठोस कदम नहीं उठाती, न ही इस पर किसी प्रकार के कोई कड़े कानून लाती है। कठोर कानून नहीं होने की वजह से सट्टा खिलवाने वाले आसानी से सट्टे-जुएं का प्रचार कर उसे लोगों के बीच में खिलवाते हैं।

रिकेश बैरागी

इन सारे सट्टा बाजार और जुआ बाजार को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है और सट्टेबाजी के सौदागर भरपेट रुपया पैसा बांट देते है। तभी तो पुलिस और प्रशासन सट्टे के खायवालो के सामने या ऑनलाइन गेम के मालिक के सामने नतमष्तक होते हैं।

हालांकि, केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैश्णव ने कहा है कि, ऑनलाइन, जुए और सट्टे बाजी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कानूनी उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा है कि, पिछले वर्ष ऑनलाइन सट्टा और जुएं की 1097 बेबसाइट्स् पर प्रतिबंध लगाया था।

बहरहाल, जुएं और सट्टे की वेबसाइट्स को बंदकर देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या को समझ कर सरकार समाधान के ऐसे सुझावो को सशक्त करे की समाज में सट्टा या जुआ मानसिकता का सफाया हो जाएं। जिसके लिए सिर्फ सरकार को विचार ही नहीं केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर सट्टे और जुएं के विरोध में कड़े कानून प्रस्तावित करने होंगे, और देश के समाज को एकजुट होकर सट्टा मानसिकता को समाप्त करने के सफल प्रयत्न करने होंगे।

जिला कलेक्टर का लगातार स्वास्थ्य केंद्रों का औचिक निरक्षण

माही की गूंज, पेटलावद।

झाबुआ जिले में नवागत कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के द्वारा लगातार जिले में शासकीय स्वास्थ्य केंद्रो का निरीक्षण किया जा रहा है। बुधवार को पेटलावद सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और डिलीवरी महिलाओं से बातचीत की। अस्पताल की और से डिलेवरी महिलाओं को भोजन, नाश्ता के संबंध में भी महिलाओं से बातचीत की गई। महिलाओं ने भी संतोष प्रकट किया। वही जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पेटलावद सिविल अस्पताल में डायग्नोसिस मशीन के बारे में समस्याओं से अवगत करवाया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने डायग्लोसिस मशीन में आ रही परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया ।

नेशनल लोक अदालत प्रचार के लिए वाहन को किया रवाना

माही की गूंज, झाबुआ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वाधान में 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष-2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के द्वारा 6 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रचार वाहन न्याय सारथी सहित बैंक, विद्युत विभाग, नगरपालिका के प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर न्यायालय परिसर झाबुआ से रवाना किया।

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने कहा कि, हम नेशनल लोक अदालत के आयोजन से पूर्व इसके प्रचार-प्रसार के लिए एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। यह मुहिम न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि दूर-दराज के गांवों तक फैली होगी। हमारा लक्ष्य है कि, लोक अदालत की अवधारणा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि, वे अपने विवादों का निपटारा गतिशील, निष्पक्ष एवं कम खर्चीले तरीके से करा सकते हैं। हमारे

प्रचार वाहन शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और अन्य जनसमुदायों में जाकर लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। साथ ही उन्हें आगामी लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि, लोक अदालत में अपने मामलों को सुलह-समझौते एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण कर उन्हें कोर्ट फीस वापिस के साथ-साथ एक छायादार, फलदार पौधा न्याय वृक्ष के रूप में भेंट स्वरूप दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न कोई हारता है और न कोई जीतता है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से न्याय की जीत होती है। इसमें दीवानी मामले, चेक बाउंस, बिजली चोरी, पारिवारिक विवाद और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का त्वरित निराकरण किया जाता है। यहां लिए गए निर्णय की कोई अपील नहीं होती, जिससे विवादों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इस प्रचार वाहन के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी पेम्पलेट का भी वितरण किया जायेगा।

9 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायालय झाबुआ में 8 खण्डपीठें, तहसील न्यायालय पेटलावद में 4 खण्डपीठें एवं तहसील थांदला में 2 खण्डपीठों का गठन किया गया हैं।

कलेक्टर ने शिव नर्सरी का किया अवलोकन

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा रायपुरिया क्षेत्र में एमआईडीएस संरक्षित खेती योजना अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के हितग्राही शिव नर्सरी का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नर्सरी में संरक्षित खेती के माध्यम से तैयार किए जा रहे पौधों एवं आधुनिक तकनीकों का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया कि, उक्त परियोजना लगभग 25 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई है। जिसमें हितग्राही को शासन की योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ है। योजना के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र में आधुनिक नर्सरी स्थापित कर विभिन्न फसलों की गुणवत्तायुक्त सिडलिंग तैयार की जा रही है।

हितग्राही द्वारा बताया गया कि, नर्सरी में संरक्षित वातावरण एवं कोकोपीट तकनीक का उपयोग कर पौध तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में मिर्ची की सिडलिंग तैयार की जा रही है, जिनकी बिक्री इसी वर्ष से प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि, संरक्षित खेती तकनीक के कारण गर्मी के मौसम में भी लगभग 45 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार हो रहे हैं।

हितग्राही ने जानकारी दी कि, वर्तमान में प्रति पौधे पर लगभग 25 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे आर्थिक आय में वृद्धि हो रही है। कलेक्टर ने संरक्षित खेती एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि, इस प्रकार की योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अन्य किसानों को भी उद्यानिकी एवं संरक्षित खेती योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने नर्सरी की व्यवस्थाओं एवं तकनीकी उपयोग की सराहना करते हुए उद्यानिकी विभाग को किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

मवेशी हाट बाजार का शुभारंभ, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

माही की गूंज,करवड। अरुण पाटीदार

कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन, करवड तथा वागधरा संस्था के संयुक्त प्रयासों से ग्राम पंचायत करवड के नेतृत्व में हाट बाजार का शुभारंभ किया गया। यह पहल क्षेत्र के छोटे किसानों, पशुपालकों एवं व्यापारियों को एक सशक्त मंच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में आसपास की ग्राम पंचायत करवड ,मोर, गंगाखेड़ी, मोई चारणी, घूंघरी, रुणजी, मॉडर्न, गोदड़िया एवं गेहडी, की सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत करवड के सरपंच विकास बाबूलाल गामड़ ने की। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष जमना कटारा तथा वागधरा संस्था के प्रतिनिधि पी.एल. पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सरपंच विकाश गामड ने हाट बाजार में आए सभी व्यापारियों का स्वागत करते हुए उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि, इस प्रकार की पहल आदिवासी अंचल के किसानों एवं छोटे व्यापारियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि, संगठन निस्वार्थ भाव से सरकार और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कर रहा है, जिससे भविष्य में सकारात्मक एवं दीर्घकालीन परिणाम देखने को मिलेंगे।

वागधरा संस्था के प्रतिनिधि श्री पी.एल. पटेल ने संस्था एवं संगठन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि, हाट बाजार के माध्यम से ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित एवं सुलभ दरों पर उपलब्ध होंगी। साथ ही किसानों और व्यापारियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। संगठन के अध्यक्ष जमना कटारा ने संगठन की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि, संगठन के माध्यम से समुदाय को एक सशक्त मंच प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसके लिए वागधरा संस्था के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान दिनेश डिंडोर ने अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संचालित हाट बाजारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि, ऐसे प्रयासों से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने हाट बाजार के सुचारू 5 संचालन एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ÷हाट को सुरक्षा समिति÷ के गठन की जानकारी भी दी।

हाट बाजार में विभिन्न व्यापारियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया। साथ ही पशु व्यापारियों द्वारा गाय, भैंस, बकरी एवं बैल आदि पशुओं को भी बिक्री हेतु प्रस्तुत कर किया गया। शुभारंभ के उपरांत पशुओं की बोली प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई, जिसमें स्थानीय व्यापारियों एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मोहन भूरिया ने किया।

कुल्फी निर्माण इकाइयों व फल गोदामों का निरीक्षण कर लिए नमूने

माही की गूंज, झाबुआ।

खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नापतोल विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेघनगर एवं थांदला क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान कुल्फी निर्माण इकाइयों एवं फल गोदामों की जांच कर आवश्यक नमूने लिए गए तथा संबंधित संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेलसिंह मोरी ने बताया कि, मेघनगर रेलवे स्टेशन के समीप पुराने गोदाम परिसर में कुल्फी निर्माण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर कुल तीन कुल्फी निर्माण कारखाने संचालित पाए गए, जहां कुल्फी निर्माण का कार्य किया जा रहा था। संबंधित संचालकों द्वारा निर्मित कुल्फी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय हेतु कमीशन के आधार पर वितरित की जाती है।

निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा कुल्फी एवं कस्टर्ड पाउडर के कुल चार नमूने जांच हेतु लिए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है।

कार्य के दौरान निरीक्षण स्थलों पर साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई तथा कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं पाए गए। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित कारखाना संचालकों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

संयुक्त टीम द्वारा थांदला क्षेत्र में मछली गली स्थित फल गोदामों का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में आम फलों को पकाने हेतु भंडारण किया जाना पाया गया। टीम द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग होने वाले कार्बाइड की जांच की गई, जिसमें मौके पर कार्बाइड का उपयोग नहीं पाया गया।

शहर के बीच मैरीज गार्डन पर खुद की पार्किंग नहीं, आए दिन लगते है जाम

प्रतिष्ठित लोगों पर नगरपालिका और प्रशासन की विशेष कृपा, आम लोगों पर गाज

माही की गूंज, झाबुआ।

यूं तो शहर की यातायात व्यवस्था ढाक के तीन पात ही रही है। लंबे समय से इसका कोई स्थाई हल जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और नगरपालिका के पास नहीं है। चूंकि यह सीजन शादी ब्याह का है तो शहर में यातायात का दबाव भी ज्यादा है। कहने को जिला प्रशासन, यातायात विभाग और नगरपालिका ने औपचारिकता पूर्ण वाहन पार्किंग बना रखी है लेकिन इन्हे व्यस्थित करने में सारा प्रशासनिक अमला हमेशा ही विफल दिखाई दिया है। शहर के बस स्टेण्ड क्षेत्र में दो पार्किंग है, लेकिन यह भी अव्यवस्थाओं का शिकार बनी हुई है। मंगलवार को फिर एक बार यहा प्रशासनिक अमला औपचारिकता करने के लिए सड़क पर उतरा। जब बस स्टेण्ड की पार्किंगों का निरीक्षण किया गया तो यहां भारी गंदगी देखने को मिली। जिसके बाद एसडीएम ने सफाई के निर्देश दिए। दोनों ही पार्किंगों में कुछ खास बदलाव नहीं किया गया। गांधी प्रतिमा के पीछे वाली पार्किंग में अब सिर्फ दो पहियां वाहनों के लिए घोषणा कर दी गई तो सांची पाईंट के पीछे वाली पार्किंग में चार पहियां वाहनों के लिए जगह कर दी गई। नगरपालिका को निर्देश दिए गए कि यहां लाइट की व्यवस्था की जाए और यातायात कर्मचारी के साथ नगरपालिका का एक सफाई कर्मी स्थाई रूप से पार्किंगों में रखा जाए। इसके अलावा बस स्टेण्ड पर स्थाई पार्किंग के लिए पुर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया।

अब सवाल यह कि, बस स्टेण्ड पर स्थाई पार्किंग तो बसों के अलावा किसी भी वाहन की नहीं होती। हां यह जरूर है कि, सवारियां छोडने व लेने या पार्सल लेने के लिए आने वाले चार पहियां वाहन यहां कुछ देर जरूर खड़े रहते है, लेकिन लंबे समय के लिए यहां किसी तरह का चार पहियां वाहन देखने को नहीं मिलता। बावजूद इसके बस स्टेण्ड में चार पहियां वाहनों की स्थाई पार्किंग प्रतिबंध की गई। यह अच्छा निर्णय है लेकिन इसके फायदे अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहे है। जिन दो पार्किंगों पर सफाई और परिवर्तन किया गया है वह भी समझ से परे है। क्योंकि यह पार्किंग तो पूर्व से ही है और यहां वाहन पार्किंग भी होते है। बस फर्क इतना है कि इन पार्किंगों में स्थाई खड़े रहने वाले वाहनों को यहां से हटा दिया गया है और यहां साफ-सफाई करवा दी गई है। तो प्रशासन के इस कदम के बाद क्या शहर की यातयात व्यवस्था सुचारू हो जाएगी।

यहां भी बुरे हाल

इसके उलट झाबुआ के मुख्य बाजार में अब भी दो पहियां वाहनों की बहुतायात की वजह से जाम की स्थिति रोज देखने को मिल रही है। राजवाड़ा से चारभूजानाथ मंदिर तक अव्यवस्थित दो पहियां वाहन पार्किंग बड़ी समस्या है। आजाद चौक पर भी स्थिति गंभीर है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन और नगरपालिका क्या कदम उठाएंगे...?

बिना पार्किंग के मैरीज गार्डन

शहर के बीचो-बीच चल रहे मैरीज गार्डन भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो इन दिनों शहर के यातायात को भारी जाम में तब्दील करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे है। इन मैरीज गार्डनों में दिन के आयोजन हो या रात के हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। कारण यह है कि इन मैरीज गार्डनों के पास अपनी खुद की पार्किंग ही नही है। आयोजन में आने वाले चार पहियां व दो पहियां वाहन बीच सड़क पर ही पार्क कर दिए जाते है। जिससे आम राहगीरों को आने-जाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। शहर के राजवाड़ा के समीप स्थित मैरीज गार्डन की स्थिति तो कभी-कभी भयावह होती नजर आती है।

पैदल चलना भी दुभर

स्थानीय लोगों से जब चर्चा की गई तो वे बताते है कि, क्या करें यह तो रोज का हो गया है। जब-जब मैरीज गार्ड में कोई आयोजन होता है यातायात की स्थिति गंभीर हो जाती है। पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता नहीं बच पाता है। समारोह या आयोजन में आने वाले लोग अपनी चार पहियां वाहन बीच सड़क या सड़क के किनारे ही लगा देते है जिससे दोनों तरफ का यातायात प्रभावित होता है। आने-जाने वाले वाहनों को रास्ता भी नही मिल पाता और घंटों जाम की स्थिति बन जाती है।

आपकी क्या समस्या है

जब हमने स्थानीय लोगों से चर्चा के दौरान कहा कि, शिकायत क्यों नहीं करते? तो वह कहते है शिकायत होते ही मैरीज मार्डन का मालिक या तो सीधा शिकायतकर्ता के पास पहुंच जाता या फोन कर कहने लगता है कि, आपकी क्या समस्या है, शिकायत क्यों की। क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा है और आपसी संबंध बहुत अधिक है, और मैरीज गार्डन का मालिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। जब भी ऐसा होता या तो संबंध आड़े आ जाते या वह शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाता। सोने पर सुहागा यह कि, नगरपालिका और प्रशासन मैरीज गार्डन संचालक को शिकायतकर्ता की पूरी जानकारी और मोबाइल नंबर तक उपलब्ध करा देते है।

जिम्मेदार भी नतमष्तक

बताने वाले बताते है कि, मैरीज गार्डन संचालक जो कि शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो नगरपालिका और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार भी उसके आगे नतमष्तक है। संचालक पर कार्रवाई तो दूर की बात शिकायत के बाद यहां कोई देखने तक नहीं आता। नगरपालिका और प्रशासन का मैरीज गार्डन संचालक को इतना तगड़ा संरक्षण है कि, शिकायत होते ही पहले उसे फोन कर शिकायतकर्ता की जानकारी दे दी जाती और येन-केन प्रकारेण शिकायत को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है।

सज्जन रोड पर भी यही स्थिति

सज्जन रोड़ स्थिति मैरीज गार्डन के आस-पास भी यही स्थिति देखने को मिलती है। यहां भी मैरीज गार्ड की अपनी कोई पार्किंग नहीं है। अक्सर यहां भी आयोजन या समारोह में आने वाले लोग अपने चार पहियां वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते है जिससे यातायता बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस बीच अगर मैरीज गार्डन से प्रोसेशन निकल रहा हो या मैरीज गार्डन तक आ रहा हो तो स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और लंबा जाम लग जाता है। जबकि शहर का सज्जन रोड शहर की लाइफ लाइन माना जाता है। शहर में किसी भी आपात स्थिति में इसी मार्ग का उपयोग होता है। शहर के बीच से किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो या फिर किसी आपात स्थिति में फायर को शहर के बीच जाना हो, तो यही मार्ग सबसे अहम साबित होता है। इसके अलावा शहर की एक बड़ी आबादी के लिए भी यह मुख्य मार्ग है। जिस पर हजारों लोग गुजरते है। चूंकि यह शादी ब्याह का सीजन है और इसी रास्ते पर मैरीज गार्डन भी है जिनके पास अपनी पार्किंग भी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में शहर में कोई आपात कालीन स्थिति बनती है या कोई मरीज सिरियस स्थिति में पहुंचता है तो क्या एंबुलेंस और फायर जैसी आपात सुविधाओं के पहुंचने में बाधा नहीं उत्पन्न होगी?

कौन जिम्मेदार...?

भगवान ना करे कि कोई आपात स्थिति बने, लेकिन अगर ऐसी आपात स्थिति बनी तो क्या नगरपालिका और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार तब भी मैरीज गार्डन संचालकों को संरक्षण देंगे, उनके आगे नतमष्तक होंगे या फिर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? यह बहुत साफ है कि, शहर में इस तरह की कोई आपात स्थिति बनती है तो नगरपालिका और प्रशासनिक जिम्मेदार भी उतने ही दोषी होंगे जितना कि मैरीज गार्डन संचालक...?

क्या होगी कार्रवाई

यातायात सुधारने और पार्किंग के नाम पर कार्रवाई की आमजनता को धौंस देने वाला प्रशासन यह भी तय करे कि, शहर के बीच बने इन मैरीज गार्डन संचालकों का क्या करना है जिनके पास खुद की पार्किंग तक मौजूद नहीं है। जिनसे आए दिन आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या फिर अब भी नगरपालिका और प्रशासन के जिम्मेदार इन जैसे मैरीज गार्डन संचालकों पर कृपा पात्र बने रहेंगे।

पुलिस पर युवक के साथ मारपीट के लगे गंभीर आरोप

जनसुनवाई में हुई शिकायत, सीसीटीवी फुटेज से जांच की मांग

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद पुलिस के पास सफलता ओर विवाद ऐसे जुड़े हैं जैसे तू डाल डाल में पात पात । पहले आईपीएल सट्टे की कार्यवाही के बाद हुई चेन लूट की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तो जैसे ही लुट की घटना को पुलिस ने ट्रेस की उसके तुरंत बाद पुलिस पर थाने में युवक के साथ मारपीट के गंभीर आरोप लग गए। मामले की शिकायत जयस संगठन के पदाधिकारी के साथ झाबुआ एसपी कार्यालय पहुंच कर शिकायत दर्ज करवाई ओर मामले की जांच की मांग कर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत कर्ता के साथ जनसुनवाई में पहुंचे जयस कार्यकर्ताओ ने बताया कि आज से कुछ दिन पहले दो आदिवासी युवक बीच वाले बस स्टैंड पेटलावद से पुलिस गिरफ्तार कर थाने में ले जाकर पुलिस कर्मचारियों ने मारपीट की गई ?। जिन व्यक्तियों को मारा उनके शरीर पर मारने के निशान बेल्ट से मारने के धब्बे दिख रहे हैं और उनके परिवार जब छुड़ाने आये तो उनसे 1200 रुपए लेकर उन दो व्यक्तियों को चार घंटे बाद छोड़ दिया। संगठन की ओर से मामले को दबाने के लिए पुलिस की ओर से संगठन पर दबाओ बनाने ओर धमकी देने के आरोप भी लगा जा रहे है। दूसरी ओर पुलिस इस प्रकार की किसी भी घटना से इंकार कर रहीं हैं,थाना प्रभारी निर्भयसिंह सिंह भूरिया ने इस विषय में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मारपीट के आरोप निराधार है दोनों भाई आपस में ही लड़ रहे थे ओर एक को ओर से बहन की रकम लुट की शिकायत दर्ज करवाई गई ओर बाद में दोनों भाई ने आपस में समझौता कर थाने में लिख कर दिया जिसके बाद दोनों थाने से चले गए, मारपीट जैसी कोई बात नहीं हुई।

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से मामला हो सकता है साफ

पुलिस चौकी ओर थाने सभी सीसीटीवी से लेंस हैं और थाने के बाहर ओर अंदर होने वाली सारी गतिविधियां सीसीटीवी में कैद होती है। ऐसी स्थिति में थाने में लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच से ही मामला साफ हो सकता है कि पुलिस पर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है। अब पुलिस ओर जयस दोनों सीसीटीवी फुटेज की जांच की बात कर रहे है।

सड़क किनारे की मिट्टी से हो रहा भराव, कही किया काम कही छोड़ा

माही की गूंज, पेटलावद।

बामनिया से रायपुरिया तक बने मार्ग पर इन दिनों सड़क के दोनों ओर की पट्टी जो कि काफी खुद चुकी है ओर दुर्धटना का कारण बनते जा रही है उसे भरने का कार्य चल रहा है। वैसे तो ये कार्य सख्त मोहर्रम से किया जाना था लेकिन इस कार्य में लगी एजेंसी सड़क के किनारे भरने के लिए सड़क के पास ही पड़ी मिट्टी जेसीबी के माध्यम से उठा कर भराव करने का कार्य कर इति श्री कर रही है। वहीं सड़क के दोनों ओर एक साथ भराव भी नहीं किया जा रहा है और थोड़ी थोड़ी दूर पर सड़क किनारे पर भराव किया जा रहा है और कई स्थानों को खाली छोड़ा जा रहा जिससे दुर्घटना का भी भय बना हुआ है। कई स्थानों पर स्थिति और गंभीर है जहां कोई दुपहिया या चार पहिया वाहन सड़क से उतर जाए तो सीधे दुर्धटना का शिकार हो जाए । सड़क का निर्माण लगभग दस वर्ष पूर्व एपीआरडीसी द्वारा करवाया गया था। मार्ग निर्माण तो अच्छा हुआ जिससे सड़क आज भी व्यवस्थित है लेकिन कई स्थानों पर गड्ढे तैयार होने लगे है जिसको साइड भराव के साथ साथ रिपेयर करना जरूरी है वरना बारिश में छोटे-छोटे गड्ढे बड़े गड्ढों में तब्दील हो जाएगें।

केरम टूर्नामेंट का समापन, विजेताओं का हुआ सम्मान

माही की गूंज ,रायपुरिया/झकनावदा।

झकनावदा मे खेल भावना, प्रतिस्पर्धा और उत्साह से सराबोर केरम खेल टूर्नामेंट का समापन बड़े ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए केरम किंग के रूप में पहचान बना चुके झकनावदा के कमल पडियार ने विजय श्री हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके सटीक स्ट्राइक और संतुलित खेल ने सभी को प्रभावित किया। वहीं, उपविजेता के रूप में मनीष (मोनू) सेठिया ने भी कड़ा मुकाबला देते हुए अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया। अनुभवी खिलाड़ियों में नंदकिशोरजी देवड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी निरंतरता और अनुभव का लोहा मनवाया, जबकि युवा प्रतिभा आयुष राठौड़ ने चतुर्थ स्थान हासिल कर भविष्य की संभावनाओं की मजबूत झलक पेश की। समापन समारोह में विजेताओं और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों के खेल भावना की सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। विजेता केरम खिलाड़ीयों को प्रथम पुरस्कार नगर सेठ एवं वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र कुमार कोठारी, द्वितीय पुरस्कार जितेंद्र राठौड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष झकनावदा, तृतीय पुरस्कार राजेश कांसवा पूर्व सांसद प्रतिनिधि, चतुर्थ पुरस्कार ठाकुर परीक्षितसिंह राठौर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष आदि ने विजेता का ताज पहनाकर, चंद्रशेखर आजाद के फोटो वाला प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

चैन झपटमार चढ़ा पुलिस के हत्थे, अनाज व्यापारी के साथ हुई लूट भी कबूली

माही की गूंज, पेटलावद।

विगत दिनों पेटलावद की महावीर कालोनी में दिन दहाड़े हुई चौन लुट की घटना में पेटलावद पुलिस को सफलता मिली है। लुट की घटना को अंजाम देने वाले दो में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया। वारदात में शामिल दूसरा आरोपी फरार है जबकि पकड़े गए आरोपी ने पेटलावद की वारदात के साथ साथ अन्य दो अपराध करना भी कबूल किए जिसमें बामनिया के अनाज व्यापारी के साथ रेलवे फाटक के समीप हुई लुट ओर मारपीट की वारदात भी शामिल है। पेटलावद पुलिस की ओर से थाना प्रभारी निर्भयसिंह सिंह भूरिया ने प्रेस रिलीज जारी कर मामले का खुलासा किया । थाना प्रभारी निर्भयसिंह सिंह भूरिया ने बताया कि वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की सर्चिंग में लगी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही थी, पुलिस को मुखबिर की सूचना पर लुट में शामिल आरोपी सुनील वसुनिया निवासी खवासा को घेराबंदी कर पकड़ा गया । पूछताछ में आरोपी ने अपने दूसरे साथी रोशन माल के साथ मिल कर घटना को अंजाम देना कबूल किया। दूसरे आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है।

आरोपी से बरामद हुई लूटी हुई चेन, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस

पुलिस ने अपने खुलासे में बताया कि आरोपी सुनील वसुनिया की निशानदेही पर लूटी हुई चैन बरामद की गई। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बामनिया के अनाज व्यापारी के साथ रेलवे फाटक के समीप हुई लुट की वारदात करना भी स्वीकार किया है । पुलिस ने आरोपी को न्यायलय में पेश किया जहा से उसे जेल भेज दिया गया है ।

रायपुरिया थाना क्षेत्र में हुई लुट में पुलिस के हाथ अभी तक खाली

दो दिनों में हुई दो लुट की वारदातों में से पेटलावद थाना क्षेत्र की लुट का खुलासा पुलिस ने कर दिया लेकिन रायपुरिया थाना क्षेत्र में हुई बकरा व्यापारी के साथ हुई 70हजार की नगदी की लुट में रायपुरिया पुलिस के हाथ अभी कोई सफलता नहीं लगी है। बताया जा रहा है इस लुट की वारदात में सात लोग शामिल थे।

बेखौफ लुटेरे

नगर में कई जगहों पर सीसीटीवी लगे होने के बाद भी लुटेरे बेखौफ है और बिना किसी डर के अलग अलग तरीके से लुट की घटना को अंजाम दे रहे है। अलग अलग घटाए सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। पेटलावद में शातिर लुटेरों ने अशोका रेस्टोरेंट क्षेत्र वाली गली में भी लुट वारदात को अंजाम देते हुए युवक से चांदी की रकम ओर पैसे लुट लिए जिसका कोई अता पता आज तक नही हुआ जबकि इसी क्षेत्र में इसी प्रकार की वारदात पूर्व में भी हो चुकी है। पुलिस के सामने शातिर तरीके से लुट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को दबोचने की बड़ी चुनौती है।

संपादकीय

गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा का शासन

बंगाल में भाजपा का खेला काम कर गया। ऐसा भी नहीं है कि तीन बार से सत्ता पर काबिज बंगाल की शेरनी ममता से जनता का मोहभंग हाल-फिलहाल की घटना है। भाजपा ने दशकों से आक्रामक रणनीति से चुनावी तैयारी की है। केंद्र सरकार के तमाम संसाधनों का गाहे-बगाहे प्रयोग किया। बंगालियों को रास आने

वाले तमाम विमर्श गढ़े और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिये लाखों मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। मोदी-शाह की आक्रामक रणनीति के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ता स्तर पर गहन अभियान चले। फिलहाल, गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा का शासन हो गया है। गंगा के प्रवाह के साथ बहने वाले झारखंड को छोड़ दें तो बाकी राज्य भगवामय हैं। जहां बंगाल में पहली बार कमल खिला है, वहीं तमिलनाडु में थलापति के नाम से चर्चित सुपरस्टार विजय की दमदार एंट्री हुई है। उन्होंने भी परंपरागत राजनीतिक दलों की घोषणाओं से बढ़कर लोकलुभावने वायदे किए हैं। फलतरू दो ध्रुवीय द्रविड़ राजनीति सत्ता से बाहर हुई है। स्टालिन न केवल हारे हैं, बल्कि उनकी सरकार भी गई। छह दशक बाद राज्य में गैर द्रविड़ियन सरकार बनने जा रही है। हालांकि, अभी सत्ता में आने के लिये टीवीके को गठबंधन का सहारा लेना होगा। भाजपा के लिये भी पत्ते खेलने के अवसर हैं। जहां बंगाल, केरलम व तमिलनाडु में सत्ता विरोधी लहर में सरकारें धराशायी हुई हैं,वहीं असम में भाजपा की हैट्रिक बनी है। हेमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने भरपूर बहुमत पाया है। पुडुचेरी में फिर एनडीए सत्ता पर काबिज हुआ है। लेकिन भाजपा की इस जीत की खुशी के बीच केरलम में कांग्रेस नीत गठबंधन की वापसी हुई है। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम वाम दलों के लिये दुरूस्वप्न ही साबित हुए हैं, केरलम में उनका आखिर गढ़ भी हाथ से निकल गया है। हालांकि, केरलम में भाजपा ने तीन व तमिलनाडु में एक सीट जीतकर हिंदी बेल्ट की पार्टी के ठप्पे से मुक्त होने का प्रयास किया है।

इन विधानसभा चुनाव परिणामों का निष्कर्ष यह भी है कि अब क्षेत्रीय क्षत्रपों की मुखर आवाज कुंद हो गई है। जहां ममता,स्टालिन व विजयन सत्ता से बाहर हो गए हैं, वहीं शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक का प्रभाव भी फीका हुआ है। वर्तमान विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश का 72 फीसदी भूभाग व 78 फीसदी आबादी भाजपा शासित है। अनुमान है कि अब भाजपा 'एक देश, एक चुनाव' के मुद्दे पर मुखर हो सकती है। कयास बंगाल को लेकर भी हैं कि वहां आंदोलनों के अगुवा रहे सुवेंदु अधिकारी को सत्ता की बागडोर सौंपी जाएगी, या भाजपा कोई चौंकाने वाली पहल करती है। बहरहाल, बंगाल में भाजपा ने आक्रामक चुनावी रणनीति से महज 8 फीसदी वोट प्रतिशत की वृद्धि से 131 सीटें बढ़ा ली हैं। इतना ही नहीं टीएमसी के मजबूत गढ़ों में 53 सीटें कब्जा ली हैं। बहरहाल, पहले से ही कमजोर विपक्ष को यह परिणाम बड़ा झटका है। कांग्रेस व वाम दलों से किनारा करके चलने की ममता की महत्वाकांक्षी कोशिश का लाभ भाजपा को मिला है। हां, इतना जरूर है कि दक्षिण भारत में पकड़ बनाने के लिये भाजपा को कड़ी मेहनत करनी होगी। इस बार उसे केरल की तीन व तमिलनाडु की एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं केरलम में वाम मोर्चे के अंतिम किले का ध्वस्त होना और लगातार टकराव के मूड में रहने वाले स्टालिन की विदाई उसका उत्साह बढ़ाने वाले हैं। बहरहाल- ममता, विजयन और स्टालिन की हार से संकेत मिलता है कि कांग्रेस विपक्ष के कमजोर 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व करती रहेगी। लेकिन भाजपा को आने वाले समय में पंजाब में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, जहां आम आदमी पार्टी व कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के प्रयासों में लगे हैं। बहरहाल,विगत में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रखने वाले पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान उपजी कटुता को नियंत्रित करने के प्रयास बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के करने होंगे। निस्संदेह, लोकतंत्र में हिंसा की कोई भूमिका नहीं स्वीकारी जानी चाहिए। विश्वास करें कि नयी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध को संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

अंतरिक्ष में चीनी-अमेरिकी संघर्ष के बीच भारत

बीते बुधवार को कांग्रेस की एक सुनवाई में अमेरिकी सांसदों को बताया गया, कि चीन, अमेरिका के लिए 'अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा और प्रतिस्पर्धी' है, जो अपनी खगोलीय क्षमताओं का इस्तेमाल 'कूटनीति और सामरिक प्रभाव के एक हथियार के तौर पर' कर रहा हैय यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब चांद पर पहुंचने की इन दोनों देशों की होड़, और तेज हो गई है।

अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष को लेकर चल रही होड़ में दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले सालों में चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। जहां चीन ने अपनी पहली मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, वहीं अमेरिका के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2028 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर वापस लाना, और 2030 तक वहां एक अंतरिक्ष सैन्य अड्डा बनाना शुरू करना हैय इससे इन दोनों महाशक्तियों के बीच कड़ी टक्कर शुरू हो गई है।

'सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' में एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन के हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी ऑन यूरोप की एक सुनवाई में दी जानकारी के मुताबिक, 'जैसे-जैसे देश मानकों के मामले में अमेरिका या चीन में से किसी एक के साथ जुड़ेंगे, तो जीतने वाला देश न सिर्फ तकनीक देगा, बल्कि वह उन शर्तों को भी तय करेगा, जिनके आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा। नेटवर्क आपस में काम करेंगे, लेकिन दुनिया को किस नजर से देखा जाएगा?'

सुनवाई के दौरान फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कांग्रेसी रैंडी फाइन के अनुसार, 'जब अंतरिक्ष की बात आती है, तो वह 'चीन को लेकर बहुत चिंतित हैं, जैसा कि मुझे पता है कि और भी कई लोग हैं। मुझे लगता है कि चीन खुद को हमारे साथ युद्ध की स्थिति में देखता है। यह भी कि हम अक्सर इसे उसी नजर से नहीं देखते।'

दरअसल पिछले एक साल में अंतरिक्ष दौड़ में कई अहम घटनाक्रम देखने को मिले हैंय अमेरिका ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम का दूसरा सफल मिशन पूरा किया, वहीं चीन ने अपने 2030 के मून मिशन की तैयारी में कई अहम प्रगति की। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इंसानों को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया है।

दूसरी तरफ चीन, भारत और पूर्व सोवियत संघ सहित अन्य देशों ने चांद की सतह पर रोबोटिक मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की।

गत बुधवार को हुई इस सुनवाई का शीर्षक था, 'ऑर्बिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस रू यूएस स्पेस सिक्योरिटी'। यह सुनवाई उसी दिन हुई, जिस दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्टेमिस-टू के अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी की थी। इस कार्यक्रम में नासा मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। सुनवाई के दौरान, एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन का चीन पर आरोप था कि वह ग्लोबल साउथ में अपनी साझेदारियों का विस्तार करके अंतरिक्ष का इस्तेमाल अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कर रहा है।

जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्पेस पॉलिसी इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर स्कॉट पेस के मुताबिक, चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को मशहूर 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के जरिए आगे बढ़ा रहा है, जिसमें पार्टनर देशों को जोड़ने वाला एक बढ़ता हुआ स्पेस कंपोनेंट भी शामिल है। कैरी बिंगेन के खुलासे के मुताबिक, चीन ने 'ग्लोबल साउथ' कहे जाने वाले लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों के साथ समझौते किए हैं। बिंगेन के मुताबिक, 'वे स्पेस ग्राउंड एंटीना, ग्राउंड स्टेशन कमांड और कंट्रोल साइट लगा रहे हैं। यह बुनियादी टेक्नोलॉजी है जो उन ग्राउंड स्टेशनों और एंटीना को सरकारी सिस्टम या किसी कमर्शियल सिस्टम के साथ बातचीत करने में मदद करता है।' अमेरिकी एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन के मुताबिक, 'चीन, जहां एक तरफ अपना कमर्शियल स्पेस सेक्टर बना रहा है, वहीं उसका यह प्रोग्राम काफी हद तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। इस सुनवाई में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच हुई स्पेस रेस का भी जिक्र हुआ, जब रूस, 'सोवियत संघ' के नाम से जाना जाता था।'

20वीं सदी का ज्यादातर हिस्सा मुकाबले में गुजर गया, लेकिन हाल के सालों में हालात बदल गए हैं। इस बारे में बिंगेन के विचार हैं कि जहां रूस अभी भी एक खतरा बना हुआ है, वहीं चीन एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है, जो किसी भी आधुनिक स्पेस प्रोग्राम के इतिहास में सबसे तेज तरक्की में से एक है। कैरी बिंगेन के अनुसार, 'स्पेस में नई ऊंचाइयां छूने की दौड़ जारी हैदृअमेरिका, चीन और रूस, मिलिट्री और सुरक्षा के क्षेत्रों में स्पेस में एक-दूसरे से लगातार मुकाबला कर रहे हैं।'

ठीक से देखा जाये, तो यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। यहां रक्षा और अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञ कौशिक रे की यह बात महत्वपूर्ण है कि, 'हालांकि, भारत आर्टेमिस-टू में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन वह 'आर्टेमिस अकार्ड' का हस्ताक्षरकर्ता है, और इस तरह वह अमेरिका के नेतृत्व वाले चांद की खोज के बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। नतीजतन, आर्टेमिस-टू की सफलता उस ढांचे को मजबूत करती है, जिसमें भारत अब एक हिस्सेदार है।'

पुष्परंजन

गौरतलब है कि भारत ने पूरी शिद्दत से रूस, अमेरिका और चीन के बाद, मानव अंतरिक्ष उड़ानें लॉन्च करने वाला चौथा देश बनने का लक्ष्य रखा है। इस संदर्भ में चंद्रयान चंद्र अन्वेषण मिशनों का भी रे ने जिक्र किया। उनके मुताबिक, 'इसरो को आर्टेमिस-टू मिशन द्वारा जुटाए गए अनुभव और डेटा से फायदा होगा, जो भारत के चंद्रयान और गगनयान कार्यक्रमों के साथ-साथ लंबी अवधि की मानव अंतरिक्ष उड़ानों में इसरो की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए भी बहुत प्रासंगिक है।'

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई जमीनी मिसाइलों का विकास जारी रखे हुए है। पीएलए ने रोबोटिक भुजाओं, कैमरों और सेंसरों से लैस उपग्रह तैनात किए हैं, जो शत्रु उपग्रहों से निपटने या उनमें हस्तक्षेप करने में सक्षम हैं। चीन, इमेजिंग उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने, जैमर के जरिये उनकी क्षमता कम करने, या उन्हें 'अंधा' करने के लिए डिजाइन की गई, जमीनी लेजर प्रणालियां विकसित कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट की मानें, तो पीएलए, उपग्रह नियंत्रण प्रणालियों को हैक करने, सैन्य लामबंदी और रसद व्यवस्था को बाधित करने पर फोकस्ड है।

आर्टेमिस-टू का सहयोगी बनने से हमारी महत्वाकांक्षाओं को मजबूती मिलती है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो भविष्य की तैयारियां हम देख रहे हैं, यदि चीन और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ा, फिर भारत के लिए विकट स्थिति होगी। दोनों पक्षों में देर-सवेर अंतरिक्ष में घमासान होना तय मानिये। ऐसे में भारत किसकी तरफ होगा? यह विचारणीय विषय है!

देहरी पर न्याय की चलती-फिरती चौपाल की दस्तक

इतिहास गवाह है कि न्याय की सुगमता ही किसी शासन की सफलता की कसौटी होती है। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी 'न्याय की जंजीर' के जरिए यह संदेश दिया था कि फरियादी को दरबार तक आने की जरूरत नहीं, वह जंजीर खींचकर सीधे राजा तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। आज के लोकतांत्रिक भारत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा 'न्याय रो साथी' वाहनों को हरी झंडी दिखाना उसी 'एक्सेस टू जस्टिस' का आधुनिक और तकनीकी अवतार है। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के उस विजन को साकार करती है, जहां न्याय केवल एक भव्य इमारत तक सीमित न रहकर, सचल वाहनों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति की दहलीज तक पहुंच रहा है।

यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा इस पहल को हरी झंडी दिखाना उस विजन को धरातल पर उतारता है, जो केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का संकेत देते हैं। आज के दौर में, जब अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, तब वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने की अपील महज एक सुझाव नहीं, बल्कि समय की मांग है।

अकादमिक दृष्टि से देखें तो 'न्याय रो साथी' पहल विधि के 'प्रो-एक्टिव' स्वरूप को दर्शाती है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री रोस्को पाउंड के 'सोशल इंजीनियरिंग' सिद्धांत के अनुसार, कानून का प्राथमिक कार्य समाज के प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन बनाना है। जब न्याय 'सचल' होकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के पास पहुंचता है, तो यह 'डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस' के विचार को धरातल पर उतारता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल 'जीवन' नहीं, बल्कि 'त्वरित न्याय' और 'सम्मानजनक जीवन' की गारंटी देता है, जिसे अनुच्छेद 39ए (निरूशुल्क विधिक सहायता) धरातल पर उतारता है, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे। इसी संवैधानिक वादे की भौतिक परिणति हैदृ'न्याय रो साथी'। यह वाहन केवल एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक 'लीगल एम्बुलेंस' है, जो विवाद के 'नासूर' बनने से पहले ही मध्यस्थता के जरिए उसका 'कानूनी प्राथमिक उपचार' कर देती है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि 'न्याय तक पहुंच' एक अधिकार बना रहे, न कि कोई विशेषाधिकार। यह 'डिजिटल साक्षरता' और 'सचल न्याय' के समन्वय से ग्रामीण भारत में शोषण पर लगाम लगाने का एक सशक्त माध्यम है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वैकल्पिक विवाद समाधान को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने पर जो बल दिया है, वह वास्तव में भारतीय समाज में 'लीगल प्लुरलिज्म' की गहरी स्वीकृति है। भारत जैसे देश में, जहां पारंपरिक रूप से पंचायतों और मध्यस्थता की जड़ें ऐतिहासिक रूप से गहरी रही हैं, एडीआर उन प्राचीन पद्धतियों को एक आधुनिक संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

यह पहल पारंपरिक मुकदमेबाजी की 'जीत-हार' वाली कठोर मानसिकता को 'संवाद और समाधान' में बदलकर समय, धन और संबंधों को टूटने से बचाता है। यदि छोटे दीवानी और शमनीय मामलों का निपटारा इसी मंच पर हो, तो उच्च न्यायपालिका के पास जटिल संवैधानिक और नीतिगत विषयों के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा। इन वाहनों की सबसे बड़ी शक्ति इनका तकनीक से लैस होना है। ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये 'डिजिटल डिवाइड' को पाटते हुए न्याय का एक 'मानवीय चेहरा' प्रस्तुत करते हैं।

तकनीक का यह समावेशन केवल प्रक्रियात्मक सुगमता नहीं, बल्कि न्याय के 'संवैधानिक नैतिकता' के प्रति हमारे संकल्प को दर्शाता है। जब एक सुदूर गांव का व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी परामर्श पाता है, तो वह राज्य की न्यायप्रियता में अपना खोया हुआ विश्वास पुनर्जीवित करता है। यह 'लीगल ऑल्ट्रिज्म' (विधिक परोपकारिता) का वह स्वरूप है, जहां कानून की शुष्कता मानवीय संवेदनाओं के साथ मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करती है।

डॉ. सुधीर कुमार

न्याय की यह वैश्विक अवधारणा भारत को उन प्रगतिशील देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जहां 'एक्सेस टू जस्टिस' के मॉडल तेजी से बदल रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 'मोबाइल लीगल एड' सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच रही है, सिंगापुर 'एडीआर हब' बनकर मध्यस्थता को प्राथमिकता दे रहा है, और ब्रिटेन का 'स्मॉल क्लेम ट्रैक' बिना जटिलता के छोटे विवाद सुलझा रहा हैय ठीक वैसे ही 'न्याय रो साथी' तकनीक और गतिशीलता के समन्वय से भारत में न्याय के नए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।

यह व्यवस्था प्राचीन 'वट-वृक्ष' वाली न्याय-चौपालों का संवैधानिक और तकनीकी विस्तार है। इसे प्रभावी बनाने हेतु विधि विश्वविद्यालयों के 'लीगल एड क्लिनिक्स' को इन वाहनों से जोड़ना और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। विधिक साक्षरता के लिए जटिल भाषा के बजाय स्थानीय बोलियों और पंचतंत्र व हितोपदेश की कथाओं का सहारा लेना चाहिए।

यह पहल न्याय को ऊंची इमारतों से निकालकर सीधे 'जनता के द्वार' तक लाकर शक्ति का वास्तविक विकेंद्रीकरण करती है। अब समय 'तारीख-पर-तारीख' की सुस्त संस्कृति से निकलकर 'संवाद और समाधान' की ओर बढ़ने का है। जब न्याय स्वयं चलकर पीड़ित की देहरी तक पहुंचता है, तो राज्य की जन-कल्याणकारी छवि और अधिक प्रखर होती है। यह उस स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता कदम है, जहां अधिकारों के लिए किसी भी नागरिक को दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा।

एक दौर का चुनाव और अनेक निष्कर्ष

हालिया विधानसभा चुनावों ने राजनेताओं को एक बार फिर यह याद दिलाया है कि यहां कोई भी किला स्थायी नहीं होता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत और तृणमूल कांग्रेस की पराजय ने उस धारणा को तोड़ दिया है कि मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व अजेय होता है। ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ के बावजूद सत्ता परिवर्तन यह बताता है कि मतदाता अब नेतृत्व की छवि से आगे बढ़कर ठोस परिणामों का मूल्यांकन कर रहा है।

दक्षिण में तमिलनाडु का परिणाम शायद सबसे दिलचस्प है, जहां अभिनेता विजय की पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट बनना केवल सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि राजनीतिक रिक्तता में नए विकल्प की मांग का प्रमाण है। यह उस बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के बीच मतदाता नए नेतृत्व को परखने के लिए तैयार है।

केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति यह दिखाती है कि वैचारिक रूप से सजग माने जाने वाले राज्य भी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं, यदि मतदाता को विकल्प विश्वसनीय लगता है। इसके विपरीत असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत यह साबित करती है कि जहां शासन मॉडल स्वीकार्य है, वहां एंटी-इंकम्बेंसी भी समाप्त हो जाती है। पुदुचेरी में भाजपा गठबंधन की दूसरी बार सरकार इसी निरंतरता का एक और उदाहरण है। इन पांच राज्यों के नतीजों से साफ है कि भारत में अब कोई एक राजनीतिक ट्रेंड नहीं, बल्कि कई समानांतर ट्रेंड चल रहे हैं।

इन नतीजों को यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, तो तीन बड़े ट्रेंड सामने आते हैं। पहला है चयनात्मक एंटी-इंकम्बेंसी। यानी हर राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जहां सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक है, वहां मतदाता उसे दोहराने में संकोच नहीं करता। दूसरा है क्षेत्रीय दलों को चुनौती। यहां बंगाल का परिणाम बताता है कि मजबूत क्षेत्रीय दल भी चुनौती से परे नहीं हैं। और तीसरा है नए विकल्पों की स्वीकार्यता। तमिलनाडु में 'सिने स्टार' से 'सियासी स्टार' बने विजय का उभार यह दर्शाता है कि मतदाता नए चेहरों को मौका देने के लिए तैयार है।

इन चुनावों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि भारतीय राजनीति अब एकल नैरेटिव से संचालित नहीं होती। बंगाल में सत्ता परिवर्तन, तमिलनाडु में नए विकल्प का उभार, केरल में वामपंथियों की शिकस्त और कांग्रेस की वापसी तथा असम व पुदुचेरी में स्थिरता- यह विविधता इस बात का संकेत है कि मतदाता अब अधिक सूक्ष्म स्तर पर निर्णय ले रहा है। वह राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन अंतिम फैसला स्थानीय अनुभव और नेतृत्व की विश्वसनीयता के आधार पर करता है।

इन संकेतों की असली परीक्षा 2027 में होगी, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। समय-सीमा के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव अगले वर्ष की पहली तिमाही में संभावित हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में वर्ष के अंत में मतदान हो सकता है। लेकिन यह केवल चुनावी कैलेंडर नहीं है। यह उन राजनीतिक प्रवृत्तियों की परीक्षा है, जो अभी उभरकर सामने आई हैं।

उत्तर प्रदेश का चुनाव इन सभी ट्रेंड्स का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। यहां का जनादेश केवल राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दिशा भी तय करता है। सामाजिक समीकरण, कल्याणकारी योजनाएं, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे कारक मिलकर यहां चुनावी परिणाम तय करते हैं। बंगाल का उदाहरण दिखाता है कि सत्ता परिवर्तन संभव है, जबकि असम का उदाहरण बताता है कि निरंतरता भी संभव है। उत्तर प्रदेश इन दोनों के बीच संतुलन का मैदान होगा।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह परंपरा जारी रहेगी या मतदाता प्रदर्शन के आधार पर स्थिरता को प्राथमिकता देगा। गुजरात लंबे समय से एक राजनीतिक स्थिरता का उदाहरण रहा है। लेकिन बंगाल के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक गढ़ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यदि विपक्ष संगठित होता है और स्थानीय मुद्दे उभरते हैं, तो यहां भी मुकाबला रोचक हो सकता है।

पंजाब में राजनीति हमेशा परिवर्तनशील रही है। यहां 2027 का चुनाव इस सवाल का जवाब देगा कि क्या मतदाता बार-बार बदलाव चाहता है या अब स्थिर शासन की तलाश में है। केरल के नतीजों ने यह संकेत दिया है कि यदि विकल्प विश्वसनीय हो, तो मतदाता बदलाव से पीछे नहीं हटता। गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में चुनावी परिणाम अक्सर गठबंधन और स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर करते हैं। पुदुचेरी के नतीजों ने यह दिखाया है कि छोटे राज्यों में भी निरंतरता संभव है, यदि राजनीतिक प्रबंधन प्रभावी हो।

दिनेश भारद्वाज

इन पांच राज्यों के चुनावों ने भारतीय राजनीति का नया यथार्थ सामने रखा है। नतीजों से स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक किला स्थायी नहीं। मतदाता अब अधिक सजग और निर्णायक है और चुनाव अब केवल भावनात्मक मुद्दों से नहीं जीते जाते। 2027 के चुनाव इस यथार्थ की पुष्टि करेंगे। यह तय करेंगे कि हालिया बदलाव केवल अपवाद हैं या एक स्थायी प्रवृत्ति का हिस्सा। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता है कि वह हर चुनाव के साथ खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है। और यही प्रक्रिया 2027 में एक बार फिर देखने को मिलेगी, जहां मतदाता न केवल सरकार चुनेगा, बल्कि राजनीति की दिशा भी तय करेगा।

मुंडन कार्यक्रम में खाया खाना, 79 लोगों की बिगड़ी तबियत

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के तुर्किया गांव में मुंडन के कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 79 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इन सभी लोगों को खाना खाने के कुछ घंटे में उल्टी-दस्त सहित घबराहट और पेट दर्द की शिकायत हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद तीन एंबुलेंस को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद चार मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

वही बाकी सभी का इलाज गांव के ही पंचायत भवन सहित अन्य जगहों पर हुआ। पूरे मामले की खबर लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने करीब दस सदस्यीय स्वास्थ्यकर्मियों की टीम को गांव में भेजा। साथ ही सीएमएचओ डॉ गोविंद चौहान ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया।

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा का है मामला

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा क्षेत्र का मामला होने से उन्होंने भी जिला कलेक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मरीजों के उपचार की उचित व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। मरीजों ने बताया कि दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास उन्होंने खाना खाया था। जिसके बाद 4 बजे से तबियत बिगड़ना शुरू हुई। शुरुआत में कुछ ही लोग सामने आए थे. लेकिन देर शाम तक यह आंकड़ा काफी बढ़ गया। गनीमत रही कि किसी भी मरीज की परिस्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। सीएमएचओ डॉ गोविंद चौहान की मानें तो फिलहाल दो मरीजों का गांव में ही उपचार चल रहा है। एहतियात के तौर पर अब भी स्वास्थ्यकर्मी गांव में मौजूद है।

खाना खाने के बाद शाम में बिगड़ी लोगों की तबियत

अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बताया कि खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त होने लगे और लोगों की तबियत खराब होने लगी। वहीं एक दूसरे मरीज ने बताया कि खुशी का कार्यक्रम था। 11 बजे हमने भोजन किया और इसके बाद चार बजे तबियत खराब हो गई। जी घबराने लगा और उसके बाद उल्टी हुई। फिर हम यहां अस्पताल में आ गए।

रिहायशी इलाके में घुसा 7 फीट लंबा मगरमच्छ

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम दोबड़ा में रात कोल उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करीब 7 फीट लंबा एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। देर रात गांव की सड़कों पर उसे घूमते देख ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। ग्रामीणों की सतर्कता के चलते समय रहते विभाग को सूचना मिल गई, जिससे संभावित खतरे को टालने में मदद मिली।

मंदसौर वन मंडल की टीम ने प्रभारी पुष्कर मालवीय के नेतृत्व में वन रक्षक जितेंद्र सिंह पंवार, कादर गोंदिया और सहयोगी दीपक नगर के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के बाद मंगलवार अल सुबह उसे चंबल बैकवॉटर क्षेत्र स्थित संजीत नदी में छोड़ दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी भी ग्रामीण या मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचा। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।

घटना के बाद विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई वन्यजीव रिहायशी क्षेत्र में दिखाई दे तो घबराएं नहीं और खुद से उसे पकड़ने या भगाने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू किया जा सके।

इस जबरा फैन ने कर दिया ऐसा कमाल

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के मल्हारगढ़ तहसील के छोटे से गांव चंद्रपुरा के युवक जितेंद्र मेघवाल ने अपनी विशेष और अनोखी कला के दम पर बड़ी कामयाबी और पहचान हासिल की है। उन्होंने मशहूर अभिनेता सोनू सूद का 30 बाय 30 फीट का विशाल चित्र तैयार कर सभी को हैरान कर दिया। जितेंद्र की इस अद्भुत कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। रोजाना सुबह-शाम लगभग 3 घंटे लगन से काम करते हुए उन्होंने इस चित्र को तैयार किया है।

वायरल होने से सोनू सूद की नजर इस पर पड़ी। जिसके बाद उनकी टीम ने जितेंद्र मेघवाल से संपर्क किया और उन्हें मुंबई आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण मिलने के बाद जितेंद्र अपने साथियों के साथ मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने सोनू सूद से मुलाकात की। इस दौरान अभिनेता ने उनकी बेहतरीन कला की खूब प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित भी किया। यह पल जितेंद्र और उनके परिवार के लिए बेहद खास रहा।

खूबसूरत अंदाज में मिला मेहनत का फल

जानकारी के मुताबिक, जितेंद्र को इस 30म30 फीट के चित्र को बनाने में करीब 20 दिनों का वक्त लगा। रोजाना सुबह-शाम लगभग 3 घंटे तक की गई। मेहनत का परिणाम उन्हें बेहद खूबसूरत अंदाज में मिला।

विशेष बात यह है कि उन्होंने यह विशाल चित्र स्कार्ट आर्टश् तकनीक के जरिए ऊन के धागे से तैयार किया है। जितेंद्र इससे पहले भी 3म3 फीट का चित्र धागे से बना चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से इतना बड़ा आर्टवर्क तैयार किया है। जितेंद्र मेघवाल के पारिवारिक बैकग्राउंड को देखे तो वे एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, जिनका पूरा परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है।

टॉयलेट जाने के लिए फ्लाइओवर बनवाओ

भोपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लगातार अजूबों का शहर बनती जा रही है। भोपाल के ऐशबाग में नगर निगम ने 90 डिग्री पुल के नजदीक अजीब ही शौचालय बना दिया है। दरअसल, 90 डिग्री पुल के पास वार्ड नंबर 40 में रेलवे की जमीन पर ही नगर निगम ने सुलभ शौचालय बना दिया। सुलभ शौचालय बनकर तैयार होने वाला था कि उससे पहले रेलवे ने उसके आगे अपनी बाउंड्री वाल बना दी, बाउंड्री वॉल बनने के बाद सुलभ शौचालय वाल के अंदर चला गया जिससे अब लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

आपको बता दें कि, सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा रहा था तब नगर निगम के द्वारा क्षेत्रीय निवासियों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि यह रेलवे की जमीन है यहां पर सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं किया जाए। मगर नगर निगम के अधिकारियों ने एक न सुनी और रेलवे की जमीन पर सुलभ शौचालय बना दिया। नतीजा ये हुआ कि शौचालय जब बनकर तैयार होने वाला था तभी रेलवे ने अपनी बाउंड्री बाल खींच दी।

अब नगर निगम ने जो पैसा शौचालय बनाने पर लगाया था वह बेकार जाएगा। क्षेत्रीय लोग इस गैर जिम्मेदारी पर काफी नाराजगी जाता रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम पर उनका कहना है कि क्या नगर निगम अब इस शौचालय तक पहुंचने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज बनाएगा या फिर नीचे से अंडरपास बनाएगा?

सामाजिक कार्यकर्ता अलमास अली बोले हमने नगर निगम से शौचालय बनाने की मांग की थी मगर नगर निगम ने रेलवे की जमीन पर ही शौचालय बना दिया। अब रेलवे ने अपनी बाउंड्री वाल बना दी है इस कारण हम लोग अब शौचालय का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

घाटे से उबरने की कोशिश

भोपाल।

मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर मेट्रो में लगातार घटती सवारी और बढ़ते घाटे के बीच भोपाल और इंदौर मेट्रो ने कमाई का नया रास्ता तलाश लिया है।

अब मेट्रो सिर्फ सफर का जरिया नहीं रहेगी, बल्कि जश्न का प्लेटफॉर्म भी बनेगी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 'सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स' पहल शुरू की है, जिसके तहत प्री-वेडिंग शूट, फिल्म शूटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे आयोजन मेट्रो परिसर में किए जा सकेंगे। मेट्रो मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इससे अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। इसके लिए लोगों को एक घंटे के हिसाब से 5-7 हजार रुपए तक खर्च करने होंगे बुकिंग करीब 15 दिन पहले करानी होगी। तय नियमों और टाइमिंग का सख्ती से पालन करना होगा।

सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कुछ पाबंदियां भी तय की गई हैं। मेट्रो परिसर में शराब, बीड़ी-सिगरेट और पटाखों पर पूरी तरह मनाही रहेगी। आयोजन में शामिल होने से पहले सभी लोगों की स्टेशन पर जांच की जाएगी।

पिछले साल शुरू हुई थी भोपाल मेट्रो

भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर 2025 को हुआ था और 21 दिसंबर से इसे आम यात्रियों के लिए खोला गया था। शुरुआती दिनों में यात्रियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली, लेकिन वक्त के साथ फुटफॉल में गिरावट आई। ऐसे में अब मेट्रो एडमिनिस्ट्रेश ने कमाई बढ़ाने के लिए यह नया प्रयोग शुरू किया है।

भाजपा एमएलए का दर्द

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में भाजपा विधायक का दर्द मंच पर ऐसा उमड़ा कि दिल से जुबा पर आ गया। ये बयान जैसे ही बाहर आया वायरल हो गया। रतलाम ग्रामीण सीट से भाजपा विधायक मथुरालाल डामर ने भरे मंच से कहा कि भाजपा विधायकों के आवेदन मंत्री के पिए कचरे में फेंक देते हैं, इससे दर्द होता है।प्रदेश में 165 विधायक हैं तो छोटे-मोटे विधायक को मंत्री भी नहीं पहचानते हैं। मैं विधायक हूं.. दर्द होता है।

रतलाम विकास प्राधिकरण के नए संचालक मंडल के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में बोले डामर

दरअसल रतलाम विकास प्राधिकरण (आरडीए) के नए संचालक मंडल के शनिवार को हुए पदभार ग्रहण कार्यक्रम में रतलाम ग्रामीण सीट से भाजपा विधायक मथुरालाल डामर ने दिल की बात बोले दी जो एकदम से वायरल हो गई। क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने मंच से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से मांग को देखते हैं कहकर बात टाल दिया जाता है। फिर फाइलें कचरे में फेंक दी जाती है, दर्द होता है। मैं विधायक हूं, वे मंत्री हैं, ऊपर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सड़क की मांग की तो जवाब में कागजों का पुलिंदा थमा दिया गया।

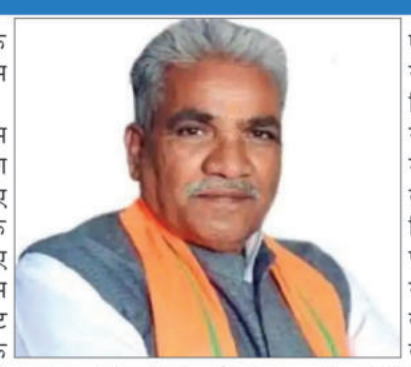

इस मौके पर विधायक डामर ने मंच पर बैठे एमएसएमई मंत्री चौतन्य काश्यप से भी सड़क बनवाने का आग्रह किया। डामर ने कहा कि जिलाध्यक्ष कहते हैं कि सीएम उनके घनिष्ठ मित्र हैं, तो सड़कें स्वीकृत करवाने में मदद करें। इस तरह से विधायक डामर की सीधी साफ बात पर मंत्री काश्यप सहित अन्य नेता भी मुस्कराते रहे। लेकिन विधायक ने दिल की बात बोलकर असल मायनों में अपना दर्द बयान कर दिया।

जैविक हाट बाजार में 53 हजार के जैविक उत्पाद बिके

माही की गूंज, रतलाम।

परियोजना संचालक आत्मा निर्भय सिंह नगेंश ने बताया कि, जिले में आयोजित जैविक / प्राकृतिक हाट बाजार में विभिन्न विकास खंडों से आए किसानों ने अपने जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों का विक्रय किया। हाट बाजार में कुल 8 जैविक कृषक अपने उत्पाद लेकर पहुंचे और उपभोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक जैविक उत्पादों की खरीदारी की।

धामनोद से आए किसान चंद्रभानु द्वारा अनाज, दालें, सब्जियां, फल एवं मूंगफली का 27050 रुपये का विक्रय किया गया। बलराम माली (धार्मेडी) द्वारा गेहू, मिर्ची, पाउडर एवं सब्जियां 6000 रुपये का, उमेश धाकड़ (बांगरोद) द्वारा घी एवं दूध 1100 रुपये का, तेजराम सांखला द्वारा हरी सब्जियां 800 रुपये का, नरसिंह कालजी सैलाना द्वारा हरी सब्जी 1000 रुपये का, दिलीप पाटीदार (करिया) द्वारा देसी घी 15000 रुपये का, बालकृष्ण तिवारी द्वारा गेहूं 2100 का एवं कालू गहलोत रावटी द्वारा जैविक उत्पाद विक्रय किए गए। जैविक हाट बाजार में कुल 53250 रुपये से अधिक के जैविक उत्पादों का विक्रय हुआ।

वन-वे व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन

माही की गूंज, मंदसौर।

शहर के व्यस्ततम सरदार वल्लभभाई पटेल चौराहा पर लागू की गई नई यातायात व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन जारी है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक दबाव कम करने के उद्देश्य से चौराहे का सर्कल हटाकर वन-वे सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है।

नई व्यवस्था के तहत अफीम गोदाम रोड, नई आबादी और संजीत नाका की ओर जाने वाले लोगों को अब सीधे मार्ग की बजाय सिटी क्राउन होटल या महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए जाना पड़ रहा है। इससे न केवल दूरी बढ़ी है, बल्कि अन्य मार्गों पर यातायात का दबाव भी बढ़ने लगा है।

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन सोमवार सुबह से धरने पर बैठे थे। सोमवार शाम को प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन मंगलवार सुबह फिर से लोग चौराहे पर एकत्र होकर विरोध में बैठ गए।

करीब 40 डिग्री तापमान की भीषण गर्मी के बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और चौराहे से बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सर्कल को छोटा करने और बैरिकेड लगाने से जाम की स्थिति बन रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह निर्णय बिना पर्याप्त योजना और जनसुनवाई के लिया गया है। उनका कहना है कि जब तक पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।

इस दौरान दीपक सिंह गुर्जर ने जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सांसद और विधायक इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन अब तक किसी ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया।

किसान पिता-पुत्र रिहा, कांग्रेस ने बग्गी में निकाला जुलूस

माही की गूंज, खंडवा।

जनसुनवाई के दौरान हंगामा करने के आरोप में जेल भेजे गए किसान पिता-पुत्र को बुधवार सुबह रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद किसान ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए मनमानी कर रहा है और सच बोलने पर उन्हें जेल भेज दिया गया।

मंगलवार को इस मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। रात में जमानत मिलने के बावजूद रिहाई बुधवार सुबह हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान पिता-पुत्र को बग्गी में बैठाकर गांधी भवन तक जुलूस निकाला और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

किसान श्याम कुमरावत और उनके पिता रामनारायण कुमरावत ने आरोप लगाया कि कलेक्टर उन्हें अपमानित करते हैं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे केवल अपने हक के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास कर रहा है।

किसान श्याम कुमरावत ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान उन्होंने रास्ते की समस्या को लेकर आवेदन दिया था। उनका कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से इस समस्या को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी ने रिश्वत ली थी, जिसके कारण उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा।

आरोप है कि इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर पिता-पुत्र को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय ले जाया गया और बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, किसानों को बिना पूर्व सूचना दिए हिरासत में लिया गया, जिसके विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया। बाद में वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद जमानत की प्रक्रिया पूरी हुई।

रिहाई के बाद किसान ने जेल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कैदियों को अत्यंत खराब भोजन दिया जाता है और रहने की सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं हैं।

किसान का यह भी कहना है कि वह तहसील से लेकर उच्च न्यायालय तक अपने पक्ष में फैसला हासिल कर चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें जमीन तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पाया है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को न्याय नहीं मिला तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं, प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई के दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई।

त्रिस्तरीय सरकार में मतभेद उजागर, स्लॉटर हाउस को लेकर विवाद

माही की गूंज, खंडवा।

नगर निगम, सांसद और विधायक सभी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से होने के बावजूद आपसी मतभेद सामने आ गए हैं। मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बुरहानपुर दौरे से जुड़ा है, जहां सांसद और विधायक ने उनसे मुलाकात कर शहर में संचालित वधशाला को शहरी सीमा से बाहर स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुरहानपुर में आयोजित एक औद्योगिक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां रोजगार और उद्योग के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी दौरान खंडवा विधायक कंचन तनवे ने मुख्यमंत्री से भेंट कर शहर में संचालित वधशाला को शहरी क्षेत्र से बाहर करने संबंधी पत्र सौंपा।

यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब खंडवा में उद्योगों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी बनी हुई है, जबकि जनप्रतिनिधि इस विषय पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

पिछले महीने प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान इमलीपुरा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मवेशियों के अवशेष बरामद किए गए थे, जिनका संबंध पास में संचालित वधशाला से जोड़ा गया। इसके बाद महापौर अमृता यादव ने वधशाला के संचालन पर रोक लगा दी थी। हालांकि, नई व्यवस्था बनाकर इसे मंगलवार से पुनः शुरू कर दिया गया।

नगर निगम के अधीन संचालित इस वधशाला को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय महापौर और उनकी परिषद द्वारा लिया गया, जबकि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक कंचन तनवे ने इसे शहर के बाहर स्थानांतरित करने की मांग उठाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थानीय स्तर का विषय है, जिसे जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय से सुलझाना चाहिए और आवश्यक प्रस्ताव बनाकर उचित निर्णय लेना चाहिए।

थाना परिसर के बाहर युवक किया आत्मदाह का प्रयास

माही की गूंज, बुरहानपुर।

कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक 35 वर्षीय युवक ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। युवक की पहचान खैराती बाजार निवासी बबलू वानखेड़े के रूप में हुई है। उसे झुलसी हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक पारिवारिक विवाद और पड़ोसियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से परेशान था। उसका कहना है कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी को लंबे समय से परेशान कर रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। युवक के अनुसार, इस मामले को दबाने के लिए उस पर महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए।

बताया गया है कि मंगलवार को इस विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से समाज की बैठक आयोजित की गई थी। आरोप है कि बैठक के दौरान युवक के परिजनों के साथ मारपीट हुई। इसके बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए युवक अपने परिवार के साथ रात में कोतवाली थाना पहुंचा।

अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने बताया कि उस पर लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे उसकी सामाजिक छवि प्रभावित हो रही थी। इसी कारण उसने आत्मदाह का प्रयास किया।

इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने बताया कि दो परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। युवक ने थाना परिसर के बाहर अपने पैरों पर आग लगाई, जिसे बाद में उसने पास स्थित पानी के हौज में कूदकर बुझा लिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि युवक के गंभीर रूप से झुलसने की सूचना सही नहीं है।

नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के अनुसार, दोनों पक्षों को समझाइश के लिए थाने बुलाया गया था। इसी दौरान युवक ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

7 वर्षीय बालिका का मिला शव, हत्या की आशंका

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के ऊन क्षेत्र में सात वर्षीय बालिका का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को आशंका है कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है।

सेगांव चौकी पुलिस को खलिहान में गेहूं के भूसे के ढेर में शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया। बुधवार दोपहर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल द्वारा शव का परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस को प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार है।

जानकारी के अनुसार, बालिका मंगलवार शाम से घर के बाहर थी। घर से कुछ दूरी पर एक विवाह समारोह भी चल रहा था, जहां वह खेल रही थी। देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए और उसकी तलाश शुरू की। करीब डेढ़ घंटे की खोजबीन के बाद उसका शव खलिहान में भूसे के ढेर में मिला।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी।

सड़कों पर कचरा, नालियां जाम, सफाई व्यवस्था पर सवाल

माही की गूंज, बड़वानी।

शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जहां साफ-सफाई के दृश्य स्वरूप को विशेष महत्व दिया जाता है, वहीं शहर की वर्तमान स्थिति इस दिशा में चुनौती बनती नजर आ रही है। कुल 12,500 अंकों में से 1,500 अंक केवल दृश्य स्वच्छता पर आधारित हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बड़वानी को शीर्ष 10 में स्थान बनाने के लिए कम से कम 85 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे, लेकिन सड़कों पर फैला कचरा इस लक्ष्य में बाधा बन सकता है।

नगर पालिका के अधिकारी सफाई व्यवस्था को बेहतर बताने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेसीबी मशीनों से सफाई कार्य कराया जा रहा है, नियमित रूप से झाड़ू लगाई जा रही है और दीवारों की रंगाई-पुताई भी की जा रही है। हालांकि, जमीनी स्थिति इन दावों से अलग दिखाई दे रही है।

शहर के बस स्टैंड पर कूड़ेदान मौजूद होने के बावजूद कचरा उसके बाहर फैला हुआ है। पाला बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय के पास नालियां कचरे से भरी हुई हैं, जबकि दशहरा मैदान में कचरा संग्रहण वाहन के आसपास गंदगी का ढेर लगा हुआ है।

इस स्थिति को लेकर विपक्ष और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। नगर पालिका में विपक्ष के नेता राकेश सिंह जाधव ने आरोप लगाया कि सफाई केवल कागजों तक सीमित है, जबकि वास्तविकता में नालियां जाम हैं और कूड़ेदान क्षतिग्रस्त पड़े हैं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि शीघ्र ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो शहर स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में वास्तविक सफाई कार्य नहीं हुआ तो इसका असर शहर की छवि पर पड़ेगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण में कचरा संग्रहण, उसके निस्तारण, नागरिकों की प्रतिक्रिया और दृश्य स्वच्छता जैसे मानकों पर अंक दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि नगर पालिका आगामी दिनों में इन व्यवस्थाओं को सुधार पाती है या नहीं।

सियासत का नया व्याकरण लिखता जनादेश 2026

2026 के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता वापसी की घटना मात्र नहीं हैं बल्कि ये देश की राजनैतिक दिशा और मतदाता के बदलते मनोविज्ञान का एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज हैं, जिसने भविष्य की राजनीति के लिए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं। इन परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या पारंपरिक वोट बैंक के गणित में उलझने वाला नहीं है बल्कि वह शासन की जवाबदेही, नेतृत्व की विश्वसनीयता और विकास के ठोस धरातल पर अपना निर्णय सुना रहा है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के तटीय मैदानों तक फैली इस राजनैतिक हलचल का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि 'भगवा' राजनीति का पूर्वी विस्तार अब अपने चरम पर है जबकि दक्षिण में क्षेत्रीय अस्मिता और नए राजनैतिक विजन के बीच एक दिलचस्प संघर्ष छिड़ गया है। ये चुनाव परिणाम उन तमाम राजनैतिक पंडितों के लिए एक सबक हैं, जो केवल पुराने आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणियां करते थे क्योंकि इस बार मतदाताओं ने एक ऐसी 'परिवर्तन की आंधी' का सूत्रपात किया है, जिसने कई दिग्गजों के राजनैतिक भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए 'महाभूकंप' को देखे बिना 2026 के इस जनादेश की व्याख्या अधूरी है। लगभग डेढ़ दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का ढहना और भाजपा का 150 सीटों के पार जाना यह दर्शाता है कि बंगाल की जनता 'सिंडिकेट राज' और 'कट मनी' की संस्कृति से ऊब चुकी थी। बंगाल का यह परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है, जहां मतदाताओं ने 'बंगाली अस्मिता' के साथ 'राष्ट्रीय विकास' के समन्वय को स्वीकार किया है। संदेशखाली जैसी घटनाओं ने शासन के प्रति जो आक्रोश पैदा किया था, वह ईवीएम के माध्यम से ज्वालामुखी की तरह फटा। भाजपा ने यहां जिस प्रकार से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया और साथ ही मतुआ एवं राजवंशी समुदायों को अपने पक्ष में संगठित किया, उसने टीएमसी के अभेद्य दुर्ग की ईंट से ईंट बजा दी। ग्रामीण बंगाल में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' और 'जल जीवन मिशन' जैसी केंद्रीय योजनाओं ने एक नया 'लाभार्थी वर्ग' तैयार किया, जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पारदर्शिता को राज्य सरकार की भ्रष्टाचार युक्त मशीनरी से बेहतर पाया। यह चुनाव परिणाम ममता बनर्जी के उस करिश्मे के अंत का भी संकेत है, जो कभी अपराजेय माना जाता था और अब बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां सुशासन और कानून-व्यवस्था ही सत्ता की एकमात्र कसौटी रह गई है।

असम की ओर रुख करें तो यहां की स्थिति बंगाल से बिल्कुल भिन्न लेकिन उतनी ही प्रभावशाली है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा की 'हैट्रिक' ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब विकास को सांस्कृतिक अस्मिता के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह एक अजेय फॉर्मूला बन जाता है। असम में भाजपा की जीत केवल सत्ता की निरंतरता नहीं है बल्कि यह उस विश्वास की पुष्टि है, जो जनता ने सरमा के प्रभावी और साहसी नेतृत्व में दिखाया है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन ने राजनैतिक भूगोल को इस तरह बदला कि घुसपैठ और बाहरी प्रभाव की राजनीति हाशिए पर चली गई और 'असमिया राष्ट्रवाद' का नया स्वरूप उभरकर सामने आया। 'ओरुनोडोई' जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं के बीच भाजपा को एक ऐसे रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसके पास उनके दैनिक जीवन की समस्याओं का ठोस समाधान है। असम का जनादेश संदेश देता है कि यदि नेतृत्व के पास विजन हो और वह जमीनी मुद्दों पर आक्रामक तरीके से कार्य करे तो जनता उसे फिर सेवा का अवसर प्रदान करती है। यहां विपक्ष की बिखरी हुई ताकत और कांग्रेस की वैचारिक शून्यता ने भाजपा की राह को और भी आसान बना दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वोत्तर में भाजपा अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक स्थायी शक्ति बन चुकी है।

दक्षिण भारत के राजनैतिक परिदृश्य में तमिलनाडु ने इस बार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। थलपति विजय के रूप में एक नए राजनैतिक सूर्य का उदय यह बताता है कि तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने द्वंद्व से मुक्ति चाहती थी। विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' द्वारा 100 सीटों का आंकड़ा पार करना एक राजनैतिक चमत्कार है, जिसने एमजीआर के उस दौर की याद ताजा कर दी, जब सिनेमा और राजनीति का संगम सत्ता की चाबी बन गया था। विजय ने खुद को केवल एक फिल्मी सितारे के रूप में नहीं, एक 'संकटमोचक' और 'युवा आइकन' के रूप में पेश किया। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को ठेंगा दिखाते हुए 'अकेले शेर' की तरह चुनावी मैदान में उतरने का जो साहस दिखाया, उसने तमिल युवाओं के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह परिणाम कमल हासन और विजयकांत जैसे पूर्ववर्ती सितारों की तुलना में कहीं अधिक गहरा है क्योंकि विजय ने 'बौद्धिक राजनीति' के बजाय 'जमीनी और मास-अपील' वाली राजनीति को चुना। तमिलनाडु का यह जनादेश द्रविड़ राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है, जहां अब 'तीसरी शक्ति' केवल संभावना नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है।

केरल का चुनाव परिणाम भी कम दिलचस्प नहीं रहा, जहां 'एक बार इधर, एक बार उधर' की पारंपरिक रीत ने पिनाराई विजयन की तमाम कोशिशों के बावजूद एलडीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया। यूडीएफ की यह प्रचंड वापसी यह दर्शाती है कि केरल का शिक्षित मतदाता भ्रष्टाचार और राजकोषीय कुप्रबंधन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। विभिन्न घोटालों ने एलडीएफ की नैतिक साख को जो चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई उसकी जनहितैषी योजनाओं से भी नहीं हो सकी। राहुल गांधी की वायनाड में सक्रियता और 'न्याय' जैसी योजनाओं के वादे ने कांग्रेस नीत यूडीएफ के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच उपजे असंतोष ने सत्ता के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। केरल का मतदाता यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी दल को 'टेकन फॉर ग्रांटेड' नहीं लेता और सत्ता की चाबी हमेशा जनता के हाथ में रहती है, जो हर पांच साल में शासन की समीक्षा बड़ी निर्ममता से करती है। पुडुचेरी जैसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश ने भी यह दिखाया कि राजनीति में स्थिरता और केंद्र के साथ तालमेल का कितना महत्व है। एन. रंगासामी की सहज छवि और भाजपा के साथ उनके गठबंधन ने मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया कि विकास के लिए केंद्र और स्थानीय सरकार का एक पटरी पर होना जरूरी है। पुडुचेरी के परिणामों ने यह साबित किया कि छोटे क्षेत्रों में व्यक्तिगत संपर्क और सामाजिक समीकरण ही हार-जीत की रेखा खींचते हैं। यहां का मतदाता प्रशासनिक गतिरोध के बजाय स्थिरता को अधिक महत्व देता है और यही कारण रहा कि गठबंधन की राजनीति ने यहां अपनी सफलता का परचम फहराया।

योगेश कुमार गोयल

पांचों राज्यों के परिणामों को यदि एक व्यापक कैनवास पर रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति अब 'परफॉर्मेंस' के युग में प्रवेश कर चुकी है। अब केवल जातिगत समीकरण बैठाकर या बड़े-बड़े विज्ञापन देकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और असम में उसकी वापसी दर्शाती है कि 'हिंदुत्व' और 'विकास' का मिश्रण अभी भी भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली तत्व है लेकिन तमिलनाडु और केरल के परिणाम यह भी सचेत करते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं और स्थानीय नेतृत्व का महत्व कभी कम नहीं होगा। इन चुनावों ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के लिए केरल में संजीवनी का काम किया है तो वहीं भाजपा के लिए दक्षिण में नए मित्र तलाशने की चुनौती पेश की है। कुल मिलाकर, 2026 के इस जनादेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता अब अधिक अपेक्षा-केंद्रित हो गया है। वह केवल यह नहीं देखता कि सरकार ने क्या किया बल्कि यह भी देखता है कि नेतृत्व कितना विश्वसनीय है और भविष्य के लिए उसके पास क्या रोडमैप है। थलपति विजय जैसे नए चेहरों का स्वागत और ममता बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं की हार बताती है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। आने वाले समय में वही दल और नेता प्रासंगिक रहेंगे जो जनता की आकांक्षाओं को समझेंगे और विकास, पहचान एवं सुशासन के बीच एक कुशल संतुलन स्थापित कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामुहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन आलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा, जोबट और आलीराजपुर जनपद पंचायत में किया गया। आलीराजपुर जनपद में कुल 57 जोड़ों का,जोबट में कुल 55 जोड़ों का और कट्ठीवाड़ा में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, जोबट विधायक श्रीमती सेना पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हजरी बाई खरत, कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संघमित्रा गौतम, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री निधि मिश्रा, प्रभारी जनपद पंचायत सीईओ आलीराजपुर एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री निर्मला कलमे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मंत्री नागर सिंह चौहान ने सभी नवदंपत्तियों को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि अब नवदंपति एक नए परिवार में प्रवेश कर रहे है सबके साथ अच्छे से रहे। उन्होंने सभी नव दंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका जीवन सुंदर, वैभवशाली, यशस्वी हो यही कामना है। उन्होंने सभी नवदंपतियों को शादी समारोह में संकल्प दिलाए जिनमें सर्वप्रथम प्रकृति संरक्षण के लिए जंगल बचाने, पौधा लगाने का संकल्प दिलाया और कहा कि कट्ठीवाड़ा श्मिनी कश्मीरश् के नाम से जाना जाता है इसलिए इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने है और पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना है। तत्पश्चात मंत्री चौहान ने सभी जोड़ो को सामूहिक रूप से नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया और कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए नशे का त्याग करे। किसी को अच्छा व्यापार,खेती किसानी, उद्योग करना है तो शासन की योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ ले।

जोबट विधायक श्रीमती सेना पटेल ने इस अवसर पर नए जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से नवदपतियों का नए जीवन का श्री गणेश हुआ है तो सभी अपने दोनों परिवार के साथ खुश रहे,जीवन भर साथ निभाना, अच्छे विचारों के साथ जीवन की शुरुआत कर जीवन को खुशहाल बनाना।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने सभी जोड़ों को उनके सुखी एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विवाह होने पर आप पूरे परिवार से जुड़ते है और दोनों परिवार को अपना कर साथ निभाना और हमेशा सम्मान करना। नवदम्पति अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े।

कार्यक्रम के अंत में मंत्री चौहान द्वारा सभी नव विवाहित जोड़ों और उपस्थित जनों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई और सभी मुख्य अतिथियों द्वारा एक-एक जोड़ों से मुखातिब होकर उन्हें आशीर्वाद दिया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम में ब्राह्मणों द्वारा गायत्री परिवार के विधि-विधान के साथ अग्नि के समक्ष सभी जोड़ों का वैवाहिक संस्कार संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नवदंपत्तियों को सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा नव दम्पत्तियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। समारोह उपरांत सभी नवदंपत्तियों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई।

विधायक ने आगजनी से हुए नुकसान का किया निरीक्षण

माही की गूंज, चंद्रशेखर आजाद नगर।

चंद्रशेखर आजाद नगर क्षेत्र के दौरे के दौरान जोबट विधायक सेना महेश पटेल बरझर ग्राम पहुंचीं, जहां उन्होंने हाल ही में आगजनी की घटना से प्रभावित पूर्व सरपंच सोमला बारिया के परिवार से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों अचानक लगी भीषण आग से परिवार का पूरा मकान एवं गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया था, जिससे परिवार गहरे संकट में आ गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए विधायक सेना महेश पटेल मौके पर तहसीलदार जितेंद्र तोमर के साथ पहुंचीं और पीड़ित परिवार को शासन से शीघ्र मुआवजा दिलाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक पंचनामा एवं राहत संबंधी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक सेना महेश पटेल ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपनी स्वेच्छा निधि से ?50,000 (पचास हजार रुपये) की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। विधायक ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं और हर संभव मदद दिलाई जाएगी।

बरझर प्रवास के दौरान विधायक सेना महेश पटेल ने ग्राम के ही पूर्व सरपंच महेश मावी से भी मुलाकात की, जो हाल ही में सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। विधायक ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, कुशलक्षेम पूछा तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने परिवारजनों को आश्वस्त किया कि आवश्यकता पड़ने पर हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

विधायक सेना महेश पटेल के इस जनसंपर्क एवं राहत दौरे के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश भाबर, विधायक प्रतिनिधि मदन डावर , सोनू वर्मा , विशाल अरोड़ा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय दौरे के दौरान पीड़ित एवं जरूरतमंद परिवारों के बीच पहुंचकर सहायता और संबल देने की विधायक सेना महेश पटेल की इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की तथा उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

वालपुर में 7 मई को लगेगी रात्रि चौपाल

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 7 मई 2026 को विकासखंड सोण्डवा की ग्राम पंचायत वालपुर में रात्रि चौपाल एवं खाटला बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि इस रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर बसे लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।

बैठक में जिले के सभी विभाग प्रमुख अपने मैदानी अमले के साथ उपस्थित रहेंगे, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके और उन्हें शासन की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस पहल से ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा इस प्रकार की रात्रि चौपाल का आयोजन प्रत्येक माह विभिन्न ग्राम पंचायतों में किए जाने की योजना है, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। यह बैठक 7 मई को शाम 6रू30 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

प्रशासन ने संबंधित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को समय पर सूचना देकर अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। प्रशासन का उद्देश्य है कि रात्रि चौपाल के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान हो सके।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने जनगणना कार्य का किया निरीक्षण

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण जारी है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने कट्ठीवाड़ा में चल रहे जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया।

उन्होंने कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति जानी। साथ ही अपनी मौजूदगी में प्रगणक द्वारा मकान सूचीकरण की ऑनलाइन गणना कराई। प्रगणक द्वारा उनसे 34 सवाल पूछे गए जिनका जवाब मकान के सदस्य द्वारा दिया गया और प्रगणक द्वारा जानकारी ऑनलाइन प्रविष्ट कर उनकी गणना पूर्ण की।

जनगणना के प्रथम चरण में भरी जा रही है यह जानकारी

जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का काम किया जायेगा। जिसमें 34 बिंदुओं में जानकारी संकलित होगी। इसमें भवन व मकान नम्बर सहित मकान की स्थिति, परिवार क्रमांक, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, मकान किराए का है अथवा स्वयं का, कमरों की संख्या, परिवार के विवाहित दम्पत्तियों की संख्या, पेयजल के मुख्य स्त्रोत, पेयजल स्त्रोतों की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्त्रोत, शौचालय की सुगमता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, रसोई घर व एलपीजी-पीएनजी कनेक्शन, खाना पकाने के लिये प्रयुक्त मुख्य ईंधन, रेडियोध्ट्रांजिस्टर व टेलीविजन की उपलब्धता, इंटरनेट सुविधा, लेपटॉपध्कम्प्यूटर की उपलब्धता, टेलीफोन, मोबाइल फोन व स्मार्ट फोन इत्यादि की उपलब्धता, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप व वैन, परिवार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अनाज, मसलन चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का व अन्य खाद्यान्न एवं मोबाइल फोन इत्यादि जानकारी शामिल है।

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने जिलेवासियों से भी अपील की कि जनगणना के लिये आने वाले प्रगणकों को सही-सही जानकारी देकर जनगणना अधिकारी कर्मचारी का सहयोग करे। आपके द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतरू गोपनीय रहेगी।

इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री निधि मिश्रा, तहसीलदार सुनील डावर, नायब तहसीलदार सुश्री सरिता बालेचा, प्रगणक सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

सब-इंस्पेक्टर ने घायल फरियादी को दी धमकी

माही की गूंज, कालापीपल।

शाजापुर जिले के कालापीपल थाना क्षेत्र से कानून और व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। खबर के प्रकाशन के बाद सब-इंस्पेक्टर मुनेश्वर भगत इस कदर बौखला गए कि अब वह खुद ही फरियादी को धमकाने पर उतर आए हैं।

जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल फरियादी इस समय अस्पताल के पीपुल्स हॉस्पिटल में जिंदगी और दर्द से जूझ रहा है, लेकिन उसे इंसाफ देने के बजाय पुलिसिया दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

चुप रहो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा

सूत्रों के मुताबिक, फरियादी को साफ तौर पर धमकाया जा रहा है कि मीडिया व पत्रकारों से मामला वापस ले ले, नहीं तो उसे और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम आदमी जाए तो जाए कहां?

हमला झेला, अब पुलिस का डर!

फरियादी पहले ही चाकू से हुए जानलेवा हमले में घायल हो चुका है। हाथ में गंभीर चोटों के बावजूद पुलिस ने सख्त धाराएं लगाने में लापरवाही दिखाई। और अब जब सच्चाई उजागर हुई, तो उसी फरियादी को डराकर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी मिलीभगत या मजबूरी

अब तक इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह चुप्पी किसी बड़ी मिलीभगत का संकेत है? या फिर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है? घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। लोगों का साफ कहना है कि अगर घायल फरियादी भी सुरक्षित नहीं, तो आम जनता का क्या होगा?

पानी पर बवाल, 60-65 गांवों के किसान सड़क पर

माही की गूंज, उज्जैन।

नर्मदा पाइपलाइन से अब तक वंचित घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया। बुधवार को करनी सेना परिवार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

किसानों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा

करीब 3 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद किसान तख्तियां लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम राजाराम करजरे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि 60 से 65 गांव आज भी पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे खेती करना मुश्किल होता जा रहा है और किसान आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं।

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे

किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर नर्मदा पाइपलाइन स्वीकृति और काम जमीन पर शुरू होता नहीं दिखा, तो 25 मई 2026 से 60-65 गांवों के किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए

एसडीएम ने ज्ञापन लेकर जल्द मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। धरना स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा सहित पुलिस बल तैनात रहा।

ओवरलोडिंग पर कलेक्टर की सख्ती

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कट्ठीवाड़ा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक वाहन को रास्ते में रुकवाकर कार्रवाई की। उन्होंने वाहन चालक को ओवरलोडिंग करने पर कड़ी फटकार लगाई और वाहन के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस तथा फिटनेस प्रमाण पत्र की जांच की, जो चालक के पास उपलब्ध नहीं पाए गए।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने वाहन में सवार यात्रियों को भी एक-एक कर नीचे उतरवाया और उन्हें समझाइश दी कि ओवरलोडिंग वाहन में सफर करना जानलेवा हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे वाहनों में यात्रा न करें और यातायात नियमों का पालन करें। मौके पर चांदपुर थाना प्रभारी श्री दिलीप चंदेल को बुलाकर वाहन के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी सुश्री निधि मिश्रा, नायब तहसीलदार सुश्री सरिता बालेचा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हर माह होगी मंडल स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैठक

माही की गूंज, आलीराजपुर।

संगठनात्मक दृष्टि से 'प्रवास' भारतीय जनता पार्टी की कार्यसंस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अंग है। यह प्रक्रिया संगठन की जड़ों को सुदृढ़ करने, कार्य की गति को तीव्र बनाने तथा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार करने का सशक्त माध्यम है। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार पार्टी की प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सभी मंडलों की मंडल स्तर पर नियमित बैठक करने के निर्देश अनुसार आलीराजपुर जिले के भाबरा, उदयगढ़ एवं बरझर मंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक का शुभारंभ संगठन के नियमित क्रम के अनुसार किया गया। जिसके साथ बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने तथा कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष मकू परवाल एवं जिला प्रभारी दिलीप पटोदिया ने मंडल की कार्यप्रगति की बिंदुवार जानकारी ली। जिसके पश्चात जिला प्रभारी पटोदिया ने प्रत्येक मंडल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रमों की स्थिति का आकलन करते हुए जहां आवश्यक हुआ वहां सुधार के निर्देश दिए। जिला प्रभारी दिलीप पटोदिया ने स्पष्ट कहा कि संगठन की मजबूती का आधार मंडल और बूथ स्तर की सक्रियता है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ कार्य करना होगा।

जिलाध्यक्ष मकू परवाल ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल राजनीतिक कार्य नहीं, बल्कि समाज सेवा और जनहित के कार्यों के माध्यम से आमजन का विश्वास मजबूत करना है। उन्होंने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन द्वारा निर्धारित सभी अभियानों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना है। साथ ही उन्होंने बूथ सशक्तिकरण, पन्ना प्रमुख व्यवस्था को मजबूत करने, लाभार्थी संपर्क अभियान को तेज करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा।

मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य सरकार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास की गाथा लिखते हुए ग्रामों फलियों से लेकर छोटे बड़े शहरों तक सभी जगहों हर आम जनमानस की हर बुनियादी एवं जनसुविधा अनुसार की जा रही मांगो को पूरा करते हुए सरकार हर मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु वचनबद्ध होकर कार्यरत है।

उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी, गरीब कल्याण, किसान हित, महिला सशक्तिकरण और युवा रोजगार से

जुड़ी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। उदयगढ़ मंडल की बैठक के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मांगीलाल चौहान का सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्वागत करते हुए बधाई दी।

बैठक में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान, भाजपा जिला प्रभारी दिलीप पटोदिया, जिलाध्यक्ष संतोष (मकू) परवाल, पूर्व विधायक माधोसिंह डावर, युवा नेता विशाल रावत, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मांगीलाल चौहान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीष शुक्ला, अजय जायसवाल सहित भाबरा मंडल अध्यक्ष नारायण अरोड़ा, बरझर मंडल अध्यक्ष लालसिंह, उदयगढ़ मंडल अध्यक्ष जीतू गुजराती, भूपेंद्र डावर, मांगीलाल चौहान सहित पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी विधायक प्रतिनिधि गोविंदा गुप्ता द्वारा दी गई।

अवैध रेत के व्यापार पर निरंकुश हुआ विभाग और प्रशासन

सड़क किनारे रेत के ढेर लगाकर किया जा रहा है अवैध व्यापार, ओवरलोड डंपरों का रोज नगर में आना-जाना

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

कहते हैं जितना बड़ा व्यापार उतना बड़ा सरकार का फायदा, लेकिन अवैध रेत के व्यापार में गंगा उल्टी बह निकली है जितना बड़ा ओर अवैध व्यापार सरकार का उतना बड़ा नुकसान ओर जिम्मेदारो का उससे कई गुना निजी फायदा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है बालू रेत के अवैध व्यापार के माध्यम से सरकार को बड़े स्तर पर राजस्व का चुना लगा कर खुद की जेब भरी जा रही हैं। जो पैसा शासन के खाते में जाना था वो जिम्मेदारो की जेब की शोभा बढ़ा रहा है। समीपस्थ आलीराजपुर जिले सहित मध्यप्रदेश के अन्य जिलों ओर गुजरात राज्य से धड़ल्ले से अवैध रेत का कारोबार खुले आम जारी है। इस अवैध व्यापार के आगे शासन, प्रशासन, पुलिस ,राजस्व विभाग सहित खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने ओर कार्रवाई करने के लिए बने खनिज विभाग की नाक के नीचे अवैध रेत का व्यापार बड़े स्तर पर किया जा रहा है जिसे न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। इन दिनों नगर सहित आसपास के क्षेत्र में देर रात से लेकर अल सुबह तक रेत से भरे ओवर लोड डंपर सड़कों पर आसानी से देखे जा सकते है। इन डंपरो में अवैध रूप से ओवर लोड रेत भरी जाती हैं तो कईयों के पास रायल्टी तक नहीं होती इसके बाबजूद बैधड़क सड़कों पर आसानी से देखे जा सकते है।

सड़क के किनारे लगे रेत के ढेर, खुलेआम अवैध रूप से हो रही सप्लाई

अवैध रेत का व्यापार किस कदर फल फूल रहा है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता की ये रेत से अवरलोड डंपर सैकड़ों किलोमीटर दूर से अवैध रूप से यहां तक बै रोक टोक पहुंच जाते हैं। लेकिन स्थाई रूप से जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उधर जिम्मेदार खनिज विभाग के अधिकारी कम्बल ओड कर घी पी रहे है ओर महिना बंदी के नाम पर इन अवैध रेत के डंपरो का आवागमन खुले आम हो रहा है। अवैध व्यापार का खेल यही खत्म नहीं होता, सैकड़ों किलोमीटर दूर से अवैध रूप से स्थानीय स्तर पर पहुंचने के बाद सड़को के किनारे अवैध रेत के ठिए पेटलावद, रायपुरिया, बामनिया ,करवड़ सहित कई गांवों में रेत के ढेर लगा कर के रेत बिना रॉयल्टी बेची जा रही है। खनिज विभाग न तो इन डंपरो को रोक पा रहा है न ही इन अवैध रेत के ठियों से बिक रही रेत पर कोई कार्रवाई कर पा रहा है।

जल्दबाजी के चक्कर में होती है दुर्घटना

रॉयल्टी चोरी ओर ओवरलोडिंग के चलते ये अवैध रेत से भरे डंपर तेज गति से चलते हुए कई बार बड़ी दुर्घटनाओं तक को अंजाम दे देते है जिसके कई उदाहरण जिले ओर आसपास के क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के माध्यम से देख चुके है और कितनी ही मौत इन दुर्घटनाओ में हो चुकी हैं। आज भी ये वाहन तेज गति से व्यस्तम मार्गो में आना-जाना कर रहे है। यहां तक कि इन वाहनों के आने-जाने के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का उपयोग करते है जो सड़के इतना वजन के लिए नहीं बनी होती ओर इन सड़कों की आयु अधिक वजन झेलने के कारण कम हो कर ग्रामीण क्षेत्र की सड़के समय से पहले ही टूट फूट जाती है।

इस संबंध में प्रभारी तहसीलदार अनिल बघेल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, इस प्रकार की जानकारी आते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी व प्रकरण खनिज विभाग को भेजे जायेगे।

डॉ. शिव दयाल सिंह की जगह जिले के नए पुलिस कप्तान होंगे देवेंद्र पाटीदार

क्या जिले की कानूनी और अपराधिक परिस्थितियां बनेगी पाटीदार के लिए चुनौती...?

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसुरी

झाबुआ जिले को 53 वें पुलिस अधीक्षक के रूप में एक नया चेहरा देवेन्द्र पाटीदार का मिला है। पुलिस विभाग में शनिवार देर रात हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद झाबुआ एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह को पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है। नए पुलिस अधीक्षक के रूप में 2016 बैच के आइपीएस अधिकारी देवेंद्र पाटीदार ने नए पुलिस अधीक्षक के रूप में जिले की कमान संभाली है। इससे पहले पाटीदार बुरहानपुर में पदस्थ थे। पाटीदार का फोकस ज्यादातर सामाजिक पुलिसिंग पर रहा है। वे धार जिले में पहले एसएसपी के पद पर लंबे समय तक रहे है। इसी को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे है कि, नवागत एसपी पाटीदार आदिवासी जिले में कार्य अनुभव के साथ जिले में आए है तो पुलिस महकमे और जिले की कानून व्यवस्था के लिए कुछ अच्छा ही होगा। बावजूद इसके जिले की भौगोलिक स्थिति, आदिवासी समाज की परिस्थितियां, जिले में आपराधिक गतिविधियां और कानून व्यवस्था पाटीदार के लिए चुनौती भरी हो सकती है?

पूर्व पुलिस अधीक्षक डॉ. शिव दयाल सिंह जिले में लगभग 7 माह तक अपनी सेवाएं देते रहे। इनके कार्यकाल में विभागीय अनुशासन पर ज्यादा जोर दिया गया। इनके नेतृत्व में पुलिस विभाग ने कई संवेदनशील मामलों का खुलासा किया। 7 माह के इस कार्यकाल में सोशल पुलिसिंग पर इतना जोर देखने को नहीं मिला। इनके पहले जिले में एसपी रहे पद्मविलोचन शुक्ल को जरूर

सामाजिक पुलिसिंग करते देखा गया। मगर उनके कार्यकाल में कुछ खास विभागीय उपलब्धियां देखने को नहीं मिली। कारण यह था कि, उन्होने पुलिस विभाग को सामाजिक विभाग ही बना डाला था। सोशल पुलिसिंग के नाम पर वे हमेशा कैमरों से घिरे रहते थे और यही कोशिश रहती थी कि, वे अखबारों में किसी न किसी तरह छाए रहे। पूर्व पुलिस अधीक्षक शुक्ल का हर कदम कुछ नया करके मीडिया में छाए रहने के लिए ही उठता दिखाई देता था।

जिले में अधिकारियों का आना-जाना लगा रहता है। कुछ अखबारों में छप कर चले जाते है तो कुछ जिलेवासियों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाते है, जिन्हे लोग वर्षों याद रखते है। अब जिले को नए पुलिस कप्तान के रूप में देवेंद्र पाटीदार मिले है। उन्होने अखबारों को दिए अपने पहले वक्तव्य में यह साफ कर दिया है कि, जनता का विश्वास जीतकर ही अपराध पर प्रभावी चोट की जा सकती है। यानि सीधे तौर पर उनका फोकस भी सोशल, सामाजिक पुलिसिंग पर रहेगा। हम उम्मीद करते है कि, वे सोशल पुलिसिंग करेंगे मगर पूर्व पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल जैसी नहीं। जिले में पुलिस अधीक्षक का काम जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधों और अपराधियों पर शिकंजा कसना होता है, ना कि सुर्खियां बटोरना, अखबारों में छपना और हमेशा कैमरे के सामने रहना। इन सब चीजों से रिवार्ड, अवार्ड, तमगे और वाहवाही पाई जा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई जा सकती। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक पुलिसिंग के साथ सख्ती भी जरूरी है, अपराधियों में पुलिस का खौफ होना भी जरूरी है और आमजन में पुलिस पर विश्वास बने। इसके बाद ही सोशल पुलिसिंग का नंबर आता है। हम उम्मीद करते है कि, जिले में पधारे नए पुलिस अधीक्षक परिस्थितियों को देखते हुए ही काम करेंगे।

बड़ा घोटाला: सहकारी संस्था अध्यक्ष सहित 7 पर मामला दर्ज

इन्दौर।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करण गृह निर्माण सहकारी संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष सहित सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि संस्था की जमीन को गलत तरीके से बेचकर करीब 3 करोड़ 37 लाख रुपये की गड़बड़ी की गई।

आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक रामेश्वरसिंह यादव के अनुसार, करण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा कम्पाउंड, तेजकरण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रामकुंवर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े पदाधिकारियों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों में विजय राठी, नम्रता राठी, अभय पुराणिक तथा ज्योति पुराणिक शामिल हैं, जो संबंधित संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं।

जांच में सामने आया कि, संस्था की जमीन को नियमों के अनुसार कलेक्टर मार्गदर्शक दर के आधार पर लगभग 3.37 करोड़ रुपए में बेचा जाना था, लेकिन आरोपियों ने इसे मात्र 50 लाख रुपए में बेच दिया। इससे शासन और संस्था दोनों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि, जमीन बिक्री से प्राप्त राशि को संस्था के हित में उपयोग करने के बजाय निजी कंपनियों और खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120बी में मामला दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा आगे की कार्रवाई कर रही है।

एआई के दुरुपयोग पर चिंता: इटली की प्रधानमंत्री की एआई तस्वीरें वायरल

रोम।

आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते दुरुपयोग ने अब विश्व के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा और छवि के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इसी क्रम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कृत्रिम रूप से तैयार की गई तस्वीरों के गलत इस्तेमाल का नया निशाना बनी हैं। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी तस्वीरों के प्रसारित होने पर गहरी चिंता जताई है और इसे लोकतंत्र व व्यक्तिगत गरिमा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है।

जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए बताया कि उनके विरोधियों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित उनकी नकली तस्वीरों को असली बताकर फैलाया जा रहा है। मेलोनी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिसने भी ये तस्वीरें बनाई हैं, उन्होंने कम से कम उन्हें दिखने में काफी बेहतर बना दिया है।

हालांकि, उन्होंने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि यह मामला केवल मजाक का नहीं है, बल्कि दुष्प्रचार का एक खतरनाक तरीका है।

उन्होंने कहा कि, आज किसी की भी छवि बिगाड़ने और झूठी खबरें गढ़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मेलोनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कृत्रिम तस्वीरें एक खतरनाक हथियार हैं, जिनका उपयोग लोगों को गुमराह करने और प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि वह एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपना बचाव करने में सक्षम हैं, लेकिन आम नागरिक इस तकनीक के हमले से खुद को नहीं बचा पाएंगे।

उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी सूचना या तस्वीर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। उन्होंने एक मूल मंत्र साझा कियाकृयकीन करने से पहले जांचें और साझा करने से पहले यकीन करें।

यह खतरा केवल इटली तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। भारतीय फिल्म जगत की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह अभिनेता आमिर खान का भी एक फर्जी वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें एक राजनीतिक दल का प्रचार करते दिखाया गया था।

लवेश स्वर्णकार पर मामला दर्ज, सहमति के साथ शारीरिक संबंध या दुष्कर्म...?

माही की गूंज, झाबुआ।

रायपुरिया निवासी लवेश स्वर्णकार के विरूद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद मिली-जुली कई चर्चाओं का दौर चल रहा है।

पुलिसिया जानकारीनुसार सर्वप्रथम सामने आया है कि, फरियादी महिला ने 3 मई को शाम 7 बजकर 48 मिनट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने पति के साथ आकर रायपुरिया थाने में दर्ज करवाई। जिसमें फरियादी महिला ने पुलिस को बताया किए मैं राजगढ़ रोड रायपुरिया रहती हूं तथा इसी मार्ग पर मोहल्ले में लवेश स्वर्णकार रहता है जो मेरे पति का दोस्त भी है। स्वर्णकार का मेरे पति के फोन पर फोन आता रहता हैं। एक दिन मेरे पति के फोन नंबर की सिम मेरे पास मेरे मोबाइल में थी, तो लवेश स्वर्णकार का मेरे फोन पर पति के नंबर पर फोन आया। इसी बीच हमारी करीब दिसंबर से बातचीत हो रही थी। तभी 5 जनवरी 2026 को मेरे पति बाहर गांव गए थे। तो सुबह करीब 5 बजे मुझे अकेला देखकर लवेश स्वर्णकार मेरे घर के अंदर आया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए व मेरा बलात्कार किया। व बोला कि यह बात अगर तेरे पति को बताएगी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। फिर आज दिनांक को भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पिछले तीन-चार दिनों से मुझे फोन कर बोल रहा है किए मेरे साथ संबंध बना। जिस पर मैंने मना किया, तो लवेश बोला किए तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद यह बात मैंने मेरे पति को बताई और अपने साथ पति को थाने लेकर आई और रिपोर्ट करती हूं। पुलिस ने फरियादी महिला की रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा 64(1), 332(बी), 351(3) में मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा उक्त जानकारी दी जा रही है।

उक्त मामला दर्ज होने के साथ ही जब रायपुरिया व जिले में यह जानकारी सार्वजनिक हुई तो कई तरह की मिली-जुली चर्चाओं का दौर सामने आ रहा है। जिसमें प्रथम वे लोग जो लवेश स्वर्णकार से किसी न किसी कारण से परेशान हुए थे व एक तरफा लवेश स्वर्णकार के विरूद्ध अपने विचार रखते हुए रायपुरिया में आपसी में चर्चा करते हैं और महिला पक्ष का केस मजबूत हो इसके लिए प्रयासरत भी है।

लवेश को पुलिस ने उसके घर से ही किया गिरफ्तार।

यहां चर्चा में सामने यह आ रहा है कि, लवेश स्वर्णकार, लोगों के साथ अपने अर्थ लाभ के लिए षड्यंत्र रचता रहता था और लोगों को परेशान करता था। ऐसे में सभी विरोधी लवेश के विरूद्ध एक पंक्ति में खड़े होकर कह रहे हैं कि, लवेश के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ, यह सही हुआ। और इसकी जमानत भी न्यायालय से जल्दी नहीं होना चाहिए की मनसा रखते हुए, फरियादी महिला के पति से संपर्क में आकर उसे हर तरीके से सहयोग देने की बात सामने आ रही है।

वहीं कुछ लोगों की चर्चा यह भी कि, यह मामला जबरदस्ती व डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने का नहीं है। अगर महिला ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमे स्वयं महिला कह रही है कि, उसका पति, लवेश स्वर्णकार का दोस्त था व उसके मोबाइल पर पति की सिम होने के बाद आपसी में महिला की बातचीत लवेश स्वर्णकार से होने लगी। तथा सुबह 5 बजे पति के नहीं होने पर महिला के साथ संबंध बनाएं। अगर वास्तविक में शारीरिक संबंध महिला के साथ बने हैं तो इस संबंध को आपसी सहमति के साथ ही शारीरिक संबंध बने होंगे की चर्चा की जा रही है। और मामले में यह भी चर्चा है कि, लवेश स्वर्णकार फरियादी के पति से दोस्ती होने के बाद भी आपसी में कुछ मनमुटाव होने पर फरियादी के पति जिस व्यवसाय को करता था उसी व्यवसाय को फरियादी के पति की दुकान के आसपास दो व्यक्ति को दुकान दिलवा कर व्यापार शुरू करवा दिया। उक्त बात का भी अंटश फरियादी के पति व लवेश स्वर्णकार के मध्य होना बताया जा रहा है।

खैर, चर्चा दोनों पक्षों की ओर से हो रही है और पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लवेश स्वर्णकार को उसके घर से ही पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया है। लवेश स्वर्णकार मामला दर्ज होने के बाद फरार न होकर पुलिस को घर पर ही मिला। इस पर भी चर्चा होने लगी कि, अगर असल में जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म लवेश द्वारा किया जाता तो, लवेश मामला दर्ज होने के बाद फरार हो जाता। लेकिन फरार न होकर लवेश का घर पर ही मिलना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। खैरए पुलिस की गिरफ्त में होकर लवेश जेल पहुंच चुका है। वहीं विरोधी भी खुश होकर अपनी खुशी मना रहे हैं। तो वहीं फरियादी महिला का पति व परिवार भी एफआईआर के बाद भी लवेश के विरूद्ध सख्त कार्रवाई हो और लंबी सजा मिले की मनसा रख रहे हैं। लेकिन यह भी चर्चा है कि, न्यायालय में फरियादी पक्ष को जबरदस्ती महिला से दुष्कर्म हुआ यह तथ्य मजबुत रूप से पेश करना होंगे, तभी लवेश की जमानत न होकर लंबे समय की सजा मिलना संभव है।

लेकिन चर्चाओं में कहा जा रहा है कि, यह संबंध अगर बने हैं तो आपसी सहमति से ही बने हैं। ऐसे में लीव इन रिलेशनशिप में रहने वाले तथा सहमति के साथ बने शारीरिक संबंधों पर न्यायालय गंभीरता से मनन कर आदेश देती है और पुरूष को दोषी नहीं माना गया है ऐसे आदेश पारित हुए है। ऐसे में अगर सहमति से संबंध बने हैं तथा फोन पर किसी प्रकार की कोई धमकियां महिला को नहीं दी जाकर दोनों तरफ से फोन आने-जाने का सिलसिला अगर लवेश स्वर्णकार की ओर से न्यायालय में पेश होता है तो माना जा रहा है कि, लवेश की जल्द जमानत होकर पुनः दोस्तों में सुलह न्यायिक फैसले के पूर्व हो जाएगी की संभावना जताई जा रही है।

खैर, इन चर्चाओं में जमानत व न्यायिक फैसले तक कौन सी चर्चा किस करवट बैठेगी यह तो आगे ही पता चलेगा। तब तक यह मामला सहमति के साथ शारीरिक संबंध बना या जबरदस्ती दुष्कर्म किया...? का संशय बना रहेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422